भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 2 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 174, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

सूर्योदय 6:26 सूर्यास्त 5:47

आज का तापमान

शिमला	10.0 न्यू	22.0 अधि
धर्मशाला	14.0 न्यू	24.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,729.27
निफ्टी	23,146.15
सोना 1,46,514	चांदी 2,10,000

न्यूज शॉर्ट्स

पांच करोड़ के कथित रिश्वत मामले में ग्रेवाल दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच करोड़ रुपए के कथित रिश्वत मामले की जांच के सिलसिले में अमरदीप सिंह ग्रेवाल को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक लिया। ईडी सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हालांकि, अमरदीप ग्रेवाल की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी का करीबी रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। इस संबंध में ईडी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों समेत चार की मौत

एजेंसी, पटना। बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। हादसा संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के समीप हुआ। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। पुलिस के अनुसार, सात बच्चे नदी में नहाने गए थे। इस दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा 25 वर्षीय सुधीर कुमार भी डूब गया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद चारों के शव बरामद किए। मृतकों की पहचान आकाश कुमार (15), प्रेम कुमार (10), सिद्धांत कुमार (16) और सुधीर कुमार (25) के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

अजय देवगन के बंगले में अवैध निर्माण पर बीएमसी की कार्रवाई

एजेंसी, मुंबई। मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शनिवार को फिल्म अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। यह कदम 10 सितंबर को जारी नोटिस और 6 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया। नगर निगम के अनुसार, जुहू की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित 7,802 वर्ग फुट के बंगले में आवश्यक अनुमति के बिना अंदरूनी बदलाव, विभाजन दीवारें बनाने और खिड़कियों में फेरबदल सहित निर्माण कार्य किए जा रहे थे। बीएमसी ने निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और अनधिकृत काम हटाने के निर्देश दिए थे। निगम के मुताबिक, आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने और आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर कार्रवाई की गई।

बाल यौन शोषण कंटेंट हटाने के लिए बने डेटाबेस : सुप्रीम कोर्ट

5 साल में 26.6 गुना बढ़े केस, बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति, यहां तक कि बच्चों का भी मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना बेतुका होगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उनकी आजादी, दोनों का ध्यान रखना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा- इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण बच्चों के लिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाना सही नहीं है। ऐसी रोक से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ऑनलाइन धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे शिकायत करने से भी डर सकते हैं।

कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट (सीएसईएएम) को पहचानने और हटाने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसा कंटेंट हटाने के दो घंटे के भीतर पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट देनी होगी।

गृह मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में पेश एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चों की अश्लील तस्वीरों और वीडियो से जुड़े मामले 2018 में 44 थे, जो 2022 में बढ़कर 1,171 हो गए। यानी 26.6 गुना बढ़े। वहीं, बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराध के मामले 2018 में 232 थे, जो 2022 में बढ़कर 1,823 हो गए। हालांकि, केंद्र ने 2022 के बाद का डेटा रिलीज नहीं किया।

डेटाबेस में कंटेंट की जांच के लिए होंगे ये इंतजाम



जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने डेटाबेस में दर्ज सामग्री की सही पहचान करने के लिए कई निर्देश दिए हैं। फोटो-वीडियो की डिजिटल पहचान होगी दर्जः डेटाबेस में कंटेंट का डिजिटल हैश और उस वेबसाइट का लिंक रखा जाएगा, जहां वह मौजूद है। तीन विशेषज्ञ करेंगे जांचः सामग्री को डेटाबेस में जोड़ने से पहले कम से कम तीन प्रशिक्षित विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से जांचेंगे कि वह बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी है या नहीं। शुरुआती जांच में सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है। दोबारा अपलोड होने पर भी पहचान होगीः सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट का डेटाबेस से मिलान कर सकेंगी। इससे वही सामग्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोबारा अपलोड होने पर भी पहचानी जा सकेगी। गलत जानकारी हटाने का इंतजामः जांच का रिकॉर्ड रखा जाएगा और डेटाबेस तक किसने पहुंच बनाई, इसकी जानकारी दर्ज होगी। समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट होगा और गलत तरीके से दर्ज सामग्री को हटाने और उसकी शिकायत करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

स्कूली पढ़ाई में शामिल होगी ऑनलाइन सुरक्षा

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी इंतजाम बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए काफी नहीं हैं। बच्चों को ऑनलाइन खतरों को पहचानना, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना और गलत व्यवहार होने पर मदद मांगना भी सिखाना जरूरी है। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सहमति, स्वस्थ रिश्तों, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, ऑनलाइन शोषण और उसकी शिकायत करने के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) और राज्य की शैक्षिक संस्थाओं से कहा कि वे बाल मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों और अभिभावक विशेषज्ञों की मदद से पढ़ाई की सामग्री तैयार करें।

उत्तराखंड में 5 साल में स्टार्टअप 700 से बढ़कर 1700 पार: मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्टार्टअप की संख्या लगभग 700 से बढ़कर 1,700 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश के युवा नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'विकसित उत्तराखंड-यात्रा जारी है' संवाद कार्यक्रम में उन्होंने उद्यमियों, किसानों और नवाचारकर्ताओं से बातचीत की तथा उनके अनुभव और सुझाव सुने। कार्यक्रम का आयोजन नियोजन विभाग और देवभूमि डायलॉग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक



- उद्यमिता व नवाचार से बढ़ रहे रोजगार के अवसर
- युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही सरकार

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय उत्पादों और युवाओं की प्रतिभा का उपयोग कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। संवाद के दौरान चंपावत के राहुल नरियाल ने सौर ऊर्जा से जुड़ी कार तैयार करने के प्रयास साझा किए। उत्तरकाशी के जयप्रकाश ने एक गाय से डेयरी व्यवसाय शुरू कर उसे विस्तारित करने की जानकारी दी। ऊधमसिंह नगर के विकास कुमार शाह ने बताया कि उनके स्टार्टअप का वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

चमोली में गुच्छी मशरूम, रोजमेरी और औषधीय वनस्पतियों की खेती से रोजगार सृजन के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लालकृष्ण आडवाणी को सीने में इंफेक्शन, अस्पताल में भर्ती



एजेंसी, नई दिल्ली। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार देर शाम सीने में इंफेक्शन के चलते दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक,उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकी घुसपैठ मारे

एजेंसी, श्रीनगर। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के पास शनिवार सुबह आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक दो आतंकी मारे गए हैं। पहले इस घटना को घुसपैठ की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे या नहीं।

सेना के मुताबिक, कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।

ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ टाला

बोले- हमें फायदा, रूस से कर चुका डीजल खरीद डील

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले कानून को फिलहाल रोक दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को इस फैसले से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर किए और कहा कि यह कदम अमेरिका के हित में है।



इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता था। इन देशों में चीन, भारत, स्लोवाकिया समेत हंगरी और अजरबैजान शामिल थे। प्रतिबंध से जुड़े कानून का मकसद रूस की कमाई के रास्ते बंद करना था, ताकि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध के लिए उसे पैसा जुटाने में मुश्किल हो। खास बात ये है कि ट्रम्प ने 9 अक्तूबर को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डीजल खरीदने की डील की थी।

ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल (लिंडसे ग्राहम एक्ट) पर 18 सितंबर को साइन किए थे। 16 सितंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे 262-159 वोटों से मंजूरी दी थी। कानून पर साइन करने के बाद ट्रंप को प्रतिबंध लगाने का फैसला 30 दिन के अंदर करना था। हालांकि, ट्रम्प ने इससे पहले ही प्रतिबंधों और टैरिफ पर छूट दे दी।

भारत के तेल आयात में रूस का 45% हिस्सा

भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। अगस्त 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 45% थी। भारत ने अगस्त में रूस से रोजाना औसतन 20.8 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था। ऐसे में रूस से तेल खरीदने पर 100% तक टैरिफ लगने का खतरा भारत के लिए चिंता की वजह था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा था कि भारत तेल की उपलब्धता और दुनिया के हालात को देखकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने का फैसला करता है।

गगनयान ने मॉड्यूल अलग करने का टेस्ट किया पास

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करने वाले सिस्टम की टेस्टिंग पूरी कर ली है। इसके बाद इस सिस्टम के डिजाइन की क्षमता की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किए गए। गगनयान का पहला मानवरहित मिशन 2026 में ही लांच करने का लक्ष्य है। गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से मिलकर बना है। दोनों मॉड्यूल एक सेपरेट सिस्टम के जरिए जुड़े होते हैं। अंबिलिकल कनेक्शनों से इनके बीच बिजली और लिक्विड की सप्लाई होती है।

लांच से पहले दोनों मॉड्यूल को एक साथ जोड़ा जाता है। मिशन के ऑर्बिट में रहने वाले चरण के खत्म होने तक ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश से पहले क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल से अलग होता है। इसके लिए कई घटनाएं तय क्रम में होती हैं। इसरो ने सेपरेशन सिस्टम के पूरे डिजाइन की पुष्टि के लिए विक्रम साराभाई सेंटर में ये परीक्षण किए। टेस्ट सेटअप में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल की एक साथ जुड़ी संरचना तैयार की गई थी। पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए इसमें बड़ी संख्या में इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। इसरो के मुताबिक, इन परीक्षणों से सेपरेशन सिस्टम के डिजाइन की क्षमता की पुष्टि हुई।

खाटूश्याम जा रही टेंपो ट्रैवलर नाले में गिरी; 8 यात्रियों की मौत, कई घायल

एजेंसी, कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। भोपाल से खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रही 25 से अधिक यात्रियों से भरी टेंपो ट्रैवलर सिमलिया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 15 फीट नीचे नाले में गिर गई।



- राजस्थान के कोटा में पेश आया हादसा, पुलिया से 15 फीट नीचे गिरी

हादसा सुबह करीब छह बजे कराड़िया टोल के पास हुआ। टक्कर से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने खिड़कियों के कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस और बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतकों में सात यात्रियों के अलावा बस चालक भी शामिल है। कई घायलों का उपचार जारी है। प्रारंभिक आशंका है कि चालक को झपकी आने से हादसा हुआ, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

नशा तस्करों की 74.12 लाख की संपत्ति फ्रीज

अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज, वित्तीय नेटवर्क तोड़ने में जुटी नूरपुर पुलिस

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए नूरपुर पुलिस ने अवैध कारोबार से जुड़ी करीब 74.12 लाख रुपए की संपत्तियां फ्रीज की हैं। नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने 15 अक्तूबर, 2026 को इस कार्रवाई की पुष्टि कर दी है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, एक मादक पदार्थ मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई। जांच के आधार पर पुलिस थाना जवाली ने 18 सितंबर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का आदेश जारी किया था।

फ्रीज की गई संपत्तियों में कांगड़ा जिले की जवाली तहसील के लभ गांव में स्थित दो मंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर शामिल है, जिसमें सात दुकानें हैं। इसकी अनुमानित



कीमत 68.99 लाख रुपये है। इसके अलावा, वर्ष 2019 में खरीदा गया एक ट्रैक्टर भी फ्रीज किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5.13 लाख रुपये है। ट्रैक्टर की खरीद के लिए धनराशि के स्रोत को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

पुलिस के अनुसार, नशा तस्करी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई के तहत अब तक सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के बाद लगभग 30.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं।

पुलिस ने कहा कि अभियान के तहत नशा तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आम जनता से नशा तस्करी और संदिग्ध संपत्तियों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करने की अपील की गई है।

एअर इंडिया ने सऊदी अरब की उड़ानों पर 24 तक बढ़ाई रोक

एजेंसी, नई दिल्ली। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सऊदी अरब के तीन प्रमुख शहरों जेद्दा, रियाद और दमाम से आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यह रोक 24 अक्तूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस फैसले से प्रभावित यात्रियों को टिकट की तारीख बदलने, वैकल्पिक एयरपोर्ट से यात्रा करने और रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है। एअर इंडिया के अनुसार, जिन यात्रियों के पास 15 अक्तूबर 2026 या उससे पहले जारी किए गए कन्फर्म टिकट हैं और जिनकी यात्रा की तारीख 9 से 25 अक्तूबर 2026 के बीच है, उन्हें विशेष सुविधा मिलेगी।

दिल्ली में सफाई व्यवस्था होगी मजबूत, रेखा गुप्ता ने एमसीडी की नई सुविधाओं का किया शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सरिता विहार में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की नई स्वच्छता सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राजधानी में घर-घर कचरा संग्रहण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के 25 वार्डों में घर-घर से कचरा उठाने के लिए 428 ऑटो टिपर, 128 ई-रिक्शा और 25 टाटा 407 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। कचरे के परिवहन के लिए 27 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, पांच रिफ्यूज कलेक्टर और 30 हुक लोडर भी व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कचरा एकत्र करने के लिए 100 कॉम्पैक्टर



- घर-घर कचरा संग्रहण को मिलेगी रफ्तार
- 250 वार्डों में आधुनिक लिटर पिकर मशीनें शुरू

बिन उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली के सभी 250 वार्डों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए बैटरी से चलने वाली आधुनिक लिटर पिकर मशीनों की शुरुआत भी की गई है।

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर मोनिका पंत, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा और निगमायुक्त संजीव खिरवार मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि नए संसाधनों से कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

यूपी में 2017 से पहले था रूल ऑफ माफिया हमने लागू किया 'रूल ऑफ लॉ' : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में रुल ऑफ माफिया था, लेकिन हमने कानून की किताब से उसे निकालकर 'रूल ऑफ लॉ' को ईमानदारी से लागू किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, नैतिक मूल्यों का पालन करने और निरंतर अध्ययन करते रहने की सीख दी। उन्होंने युवा विधि स्नातकों से गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान देने का आह्वान किया।

योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी शोध और साक्ष्यों के विश्लेषण में सहायक है, लेकिन अंतिम निर्णय मानवीय विवेक से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'एआई को सहायक बनाइए, सारथी नहीं।' उन्होंने डिजिटल साक्ष्यों और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी समझ विकसित करने पर जोर दिया।



दीक्षांत समारोह में 260 विद्यार्थियों को मिली डिग्री

लोहिया विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 260 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कुल 20 पदकों में से 13 छात्राओं और सात छात्रों ने हासिल किए। बीए एलएलबी में तेजस्विनी कौशल और एलएलएम में रूपल जायसवाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संविधान को मार्गदर्शक बनाकर न्याय और जनकल्याण के लिए कार्य करने की अपील की।

गड़बड़ी डोडला के दूध में मिला डिटर्जेंट, एफएसएसएआई ने 3 कंपनियों पर करवाया केस दर्ज

प्रियागोल्ड बिस्किट में जानवरों के चोकर का इस्तेमाल

एजेंसी, नई दिल्ली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने खाने-पीने की चीजों में गंभीर गड़बड़ी मिलने के बाद तीन बड़ी कंपनियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इनमें प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली कंपनी 'सूर्या फूड एंड एग्रो', 'डोडला डेयरी' और 'UEIR ऑर्गेनिक फूड्स' शामिल हैं।

एफएसएसएआई को बिस्किट में जानवरों के खाने वाला चोकर, दूध में डिटर्जेंट व कास्टिक सोडा और किशमिश में खतरनाक पेस्टीसाइड के अवशेष मिले हैं। एफएसएसएआई ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन तीनों कंपनियों पर मामला शुरू करने की जानकारी दी है।

एफएसएसएआई को एक ग्राहक से शिकायत मिली थी कि प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। शिकायत के बाद जब फूड सेफ्टी टीम ने सूर्या फूड एंड एग्रो के प्लांट का निरीक्षण किया, तो वहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की गंभीर कमियां सामने आईं। जांच रिपोर्ट के अनुसार कंपनी बिस्किट में फाइबर का सोर्स बढ़ाने के लिए जिस चोकर का इस्तेमाल कर रही थी, वह इंसानों के खाने के लायक नहीं था। वह चोकर मवेशियों के चारे के लिए तैयार किया गया था। एफएसएसएआई ने पहले कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था और अब अदालत में मुकदमा चलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डोडला के फुल क्रीम दूध में मिला डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा

दूसरा मामला डोडला डेयरी से जुड़ा है। एफएसएसएआई की टीम ने जांच के लिए डोडला डेयरी के 'फुल क्रीम मिल्क' का सैंपल लिया था। फूड एनालिस्ट ने शुरुआती जांच में दूध में फैट की मात्रा तय सीमा से कम पाए जाने पर इसे सब-स्टैंडर्ड यानी घटिया गुणवत्ता का घोषित किया था। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद सैंपल को 'रेफरल फूड लैबोरेटरी' भेजा गया। रेफरल लैब की जांच में खुलासा हुआ कि दूध न केवल सब-स्टैंडर्ड था, बल्कि इसमें डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा की मौजूदगी के कारण यह हेल्थ के लिए पूरी तरह 'असुरक्षित' था। लैब रिपोर्ट के आधार पर डोडला डेयरी और इसके निर्माण व मार्केटिंग से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।



पीली किशमिश में मिला पेस्टीसाइड का असर

तीसरी कार्रवाई यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ की गई है। एफएसएसएआई ने कंपनी द्वारा बेची जा रही 'येलो रेजिन्स' यानी पीली किशमिश का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट कराया था। लैब रिपोर्ट में किशमिश के अंदर तय मानकों से अधिक पेस्टीसाइड रेसिड्यू यानी कीटनाशक के अवशेष पाए गए। इसके लिए एफएसएसएआइ ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिमला में सील्ड सड़कों के परमिट शुल्क में कटौती को राज्यपाल की मिली मंजूरी

सालाना परमिट शुल्क में कटौती, छह महीने का पास मिलने से वाहन मालिकों को राहत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ले जाने के लिए परमिट शुल्क में कटौती से संबंधित विधेयक को राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। मानसून सत्र के दौरान पारित शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अधिनियम, 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद शुल्क में बदलाव को कानूनी रूप मिल गया है। इस संशोधन के माध्यम से 29 जुलाई, 2026 को जारी अध्यादेश को नियमित कानून का रूप दिया गया है। आधिकारिक अधिनियम के अनुसार, यह कानून 30 जुलाई, 2026 से प्रभावी माना गया है।

संशोधन के तहत वाहनों के सालाना पास की फीस 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, प्रतिबंधित सड़कों के लिए सालाना पास का शुल्क 5,000 रुपये से कम करके 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दरों को अध्यादेश के माध्यम से पहले ही लागू कर दिया गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था कानून का हिस्सा बन गई है।



नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को सालाना पास के साथ छह महीने का पास बनवाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पूरे वर्ष इन सड़कों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले सीमित अवधि के लिए सड़क का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को भी सालाना पास की पूरी फीस चुकानी पड़ती थी। छह महीने के पास

◆ नई व्यवस्था से शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चालकों का खर्च घटेगा

की सुविधा से वे अपनी जरूरत के अनुसार पास बनवा सकेंगे और शुल्क के बोझ को कम कर पाएंगे।

संशोधन में सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सील्ड सड़क के लिए छह महीने के पास का शुल्क 4,500 रुपये और प्रतिबंधित सड़क के लिए 2,000 रुपये रखा गया है। इससे वाहन मालिकों को पास की अवधि और सड़क की श्रेणी के अनुसार शुल्क चुकाने का विकल्प मिलेगा।

वोकेशनल शिक्षकों के सेवा लाभों में कटौती के आरोपों की होगी जांच

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों की सेवा में कथित अंतराल, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभों में कटौती के आरोपों की जांच होगी। श्रम विभाग ने शिकायत के आधार पर संबंधित कंपनी के रिकॉर्ड की पड़ताल कर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आठ सितंबर को श्रम आयुक्त से लिखित शिकायत कर आरोप लगाया था कि 31 मार्च को शिक्षकों और राज्य समन्वयकों की सेवा समाप्त होना दर्ज किया गया, जबकि उनकी दोबारा नियुक्ति छह, सात और 21 अप्रैल को दिखाई गई। एसोसिएशन का कहना है कि सेवा में इस तरह का अंतराल दर्ज होने से ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभ प्रभावित हो सकते हैं। वेतन में अंतर और कटौती को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। श्रम आयुक्त ने श्रम अधिकारी, शिमला को मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई शैक्षणिक भ्रमण से हिमाचली विद्यार्थियों ने विज्ञान, इतिहास और संस्कृति के सीखे गुर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर रही है। इसी पहल के अंतर्गत प्रदेश के 83 विद्यार्थी और शिक्षक मुंबई का पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पूरा कर लौट आए हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और देश की समृद्ध विरासत को करीब से जाना।

भ्रमण में मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा जिलों के विद्यार्थी एवं शिक्षक शामिल रहे। बच्चों ने गेटवे ऑफ इंडिया और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का दौरा किया। यहां उन्होंने मुंबई के इतिहास, स्थापत्य कला, प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से भारतीय विरासत को समझा।

विद्यार्थियों ने वंडरला वाटर पार्क में विभिन्न गतिविधियों का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें गति, बल और चाल जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझने का अवसर मिला।

विद्यार्थियों ने नेहरू विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक मॉडलों, प्रयोगों और संवादात्मक प्रदर्शनियों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीक की जानकारी प्राप्त की। तारामंडल में उन्होंने अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं के बारे में जाना। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और नई चीजें सीखने की जिज्ञासा को बढ़ावा मिला।



जालंधर और आसपास के स्थलों का भी किया भ्रमण

इससे पहले राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रदेश के 104 विद्यार्थी और शिक्षक जालंधर तथा आसपास के प्रमुख स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कर चुके हैं। विद्यार्थियों ने स्वर्ण मंदिर में सेवा, समानता और सामुदायिक सहयोग के मूल्यों को समझा। जलियांवाला बाग का दौरा कर स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित हुए। वाघा सीमा पर आयोजित समारोह के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एकता और सीमाओं के महत्व को जानने का अवसर मिला।

दिवाली से पहले शिमला में खाद्य सुरक्षा जांच, मिठाइयों में मिली गंदगी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। त्योहारी सीजन में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिमला शहर में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को विभाग की टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ मिठाई की दुकानों में कॉकरोच पाए गए, जबकि कई जगह गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ रखे हुए मिले। दुकानों में मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री खुले में रखी गई थीं। इससे उनके दूषित होने की आशंका जताई गई।

निरीक्षण के दौरान कुछ मिठाइयां खराब पाई गईं। विभाग की टीम ने इन्हें मौके पर ही नष्ट करवा दिया। खराब फल भी कूड़ेदान में फेंकवाए गए। दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

त्योहारी सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, दुकानों और खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली इकाइयों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां खाद्य सामग्री असुरक्षित या खराब मिलती है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिवाली तक यह अभियान जारी रहेगा। जांच के लिए लिए गए मिठाइयों और पनीर के कुछ नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जहां कमियां पाई गई हैं, वहां दुकानदारों को नोटिस जारी कर सुधार करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी विजया ने लोगों से त्योहारों के दौरान मिठाइयां खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक चमकदार और गहरे रंग वाली मिठाइयों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कारोबारी खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

जुन्गा स्कूल के वार्षिक समारोह में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बढ़ाया उत्साह

मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, शिक्षकों की सराहना की और क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने का दिया आश्वासन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जुन्गा स्थित क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए विद्यालय के विकास के लिए स्कूल समिति को 25 हजार रुपये देने की घोषणा की। समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।



◆ जुन्गा में शिक्षा और विकास कार्यों को गति देने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया जोर

समारोह को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना धैर्य, लगन और समर्पण का कार्य है। शिक्षकों को बच्चों की आयु और समझ के अनुरूप विषयों को बार-बार समझाकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है।

मंत्री ने कहा कि क्योंथल कॉन्वेंट स्कूल ने तीन बच्चों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और आज यह बेहतर मुकाम हासिल कर चुका है। यह विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों को योग्य नागरिक बनाना और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना भी है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ पढ़ाई करने का आह्वान किया। साथ ही विद्यालय प्रबंधन को स्कूल की आवश्यकताओं और विकास कार्यों में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जुन्गा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला क्षेत्र है और प्रदेश सरकार इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और लंबित योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। आईजीएमसी शिमला और अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

समारोह के दौरान मंत्री ने शैक्षणिक प्रदर्शन और विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं और उचित मांगों का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक ठाकुर, स्कूल संस्थापक एवं प्रधानाचार्य महेंद्र शर्मा, बीडीसी अध्यक्ष ताराचंद, उपाध्यक्ष मेहतेंद्र, जुन्गा पंचायत प्रधान रामलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

राठौर ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से हटाने की उठाई मांग

◆ मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में कांग्रेस ने मतियाना में प्रदर्शन कर की नारेबाजी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के क्यार-मतीयाना जोन की बैठक मतियाना में एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी सचिव एवं प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान डीसीसी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल और बीसीसी अध्यक्ष ठियोग संजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में निर्वाचित पंचायत प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, पंचायत कांग्रेस अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया।

बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की आशंका है। इस मुद्दे पर रोष जताते हुए नेताओं ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की।

बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। उन्होंने मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।

प्रदर्शन में ममता ठाकुर, टेक चंद भैक, शीतल भैक, संगीता, रंजना, मंजू, कृष्ण पाल, दीवान चंदेल, इंदर सिंह कंवर, संदीप शर्मा, निशांत, बीडीसी अध्यक्ष नवीन काल्टा, रोशन लाल, माहेश्वरी देवी, लाल चंद, रणजीत कंवर, रविंदर कंवर, रीना कश्यप और चेत राम शर्मा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रामपुर को जिला बनाने की मांग तेज सभी दलों से एकजुट होने का आह्वान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर आयोग के गठन के बाद रामपुर को जिला बनाने की मांग फिर तेज होने लगी है। एचपीएमसी के निदेशक एवं सराहन वार्ड के पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेश धीमान ने सभी राजनीतिक दलों और क्षेत्रवासियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मांग के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हित में सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी।

भूपेश धीमान ने 'आओ मिलकर हाथ मिलाओ, मतभेद भुलाओ और रामपुर को जिला बनाओ' के संकल्प के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से रामपुर को जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने नए जिलों के गठन सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आयोग गठित किया है। ऐसे में क्षेत्रवासियों को अपनी मांग मजबूती से सरकार के समक्ष रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति के लिहाज से रामपुर जिला बनने के लिए उपयुक्त है। रामपुर का संपर्क शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों से है। आउटर सिराज, आनी, करसोग और किन्नौर के निचले क्षेत्रों के लोगों के लिए रामपुर महत्वपूर्ण केंद्र है। जिला मुख्यालय दूर होने के कारण लोगों को सरकारी



◆ 2016 से उठ रही मांग, भौगोलिक स्थिति और जनसुविधाओं के आधार पर रामपुर को जिला बनाने की पैरवी

कामकाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

धीमान ने कहा कि सर्दियों में आउटर सिराज के कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क लगभग चार महीने तक प्रभावित रहता है। रामपुर को जिला बनाने से लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिल सकेंगी। इससे समय और धन की बचत होगी तथा क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि विधायक के नेतृत्व में इस मांग को आगे बढ़ाया जाएगा और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी। जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।

जाखू मंदिर में 20 साल से मुस्लिम कारीगर बना रहे दशहरे के पुतले

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन आकर्षण का केंद्र रहता है। इन पुतलों को तैयार करने में मेरठ के मुस्लिम कारीगर पिछले करीब 20 वर्षों से योगदान दे रहे हैं। उनकी मेहनत आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है। कारीगर मोहम्मद अजीम अपने साथियों के साथ इन दिनों पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि विशाल पुतले तैयार करने में करीब एक महीने का समय लगता है। इस दौरान कारीगरों को दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। इस बार जाखू मंदिर में रावण का पुतला 45 फीट ऊंचा, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले करीब 40-40 फीट ऊंचे होंगे। अजीम की टीम जाखू मंदिर के अलावा सुन्नी, संकटमोचन और जुन्गा सहित शिमला के अन्य क्षेत्रों में भी दशहरे के लिए पुतले बनाती है। मंदिर परिसर में कारीगरों के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। इस काम से उन्हें रोजगार मिलता है और परिवार का पालन-पोषण होता है। मोहम्मद अजीम ने बताया कि वह करीब 20 वर्षों से शिमला आ रहे हैं और उन्हें यहां हमेशा लोगों का सहयोग व अपनापन मिला है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए।

एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को राकेश जमवाल ने तथ्यों से दी चुनौती

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता के बीच भ्रम पैदा कर रही है।

जमवाल ने कहा कि मतदाता सूची के प्रारूप में नाम नहीं होना और अंतिम रूप से मताधिकार से वंचित होना दो अलग-अलग विषय हैं। प्रारूप सूची जारी होने के बाद दावे, आपत्तियां, दस्तावेजों का सत्यापन और नियमानुसार सुधार की प्रक्रिया होती है। इसलिए प्रारूप सूची में नाम नहीं होने को सीधे मताधिकार छिनने का प्रमाण बताना उचित नहीं है।

उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं लेखक सुरजीत एस. भल्ला के द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विश्लेषण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2024 में लगभग 7.3 करोड़ युवा मतदाता पंजीकृत नहीं थे। उनके अनुसार, मतदाता पंजीकरण से जुड़ी कमियों को भी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

भाजपा विधायक ने कांग्रेस से सवाल किया कि एसआईआर के दौरान कितने पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं और इसके समर्थन में क्या प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि यदि



भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल

किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और नियमानुसार सुधार होना चाहिए।

जमवाल ने कहा कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना और मृत, अपात्र अथवा दोहरे पंजीकरण जैसी त्रुटियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ठीक करना आवश्यक है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को आरोप-प्रत्यारोप के बजाय प्रमाणों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है।

शिमला में चिट्टा तस्करी के दोषी को दो साल की सजा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने मनोज कुमार निवासी रोहड़ू को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, बालूगंज थाना में दर्ज अभियोग संख्या 14/2022 के तहत सात जनवरी 2022 को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी मनोज कुमार के कब्जे से 24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 16 अक्टूबर 2026 को मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। शिमला पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाने और न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने पर जोर दे रही है। नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

जनसुविधा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने लंबित विकास कार्य एक वर्ष में पूरे करने का रखा लक्ष्य

बागी में खुला पशु औषधालय, विकास कार्यों को मिलेगी गति

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बागी पंचायत में करीब 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित पशु औषधालय का लोकार्पण किया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब उन्हें अपने पशुओं के उपचार के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।



शिक्षा मंत्री रोहित ने जनप्रतिनिधियों संग पशु औषधालय का किया लोकार्पण

पशुपालकों को घर के नजदीक मिलेंगी सुविधाएं : जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बागी पंचायत में पशु औषधालय का निर्माण क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग थी। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और आवश्यक सेवाएं लोगों के घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

193 सड़कों से मजबूत होगा संपर्क : रोहित ठाकुर ने बताया कि बागी और रत्नाड़ी पंचायतों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए 193 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। बर्फबारी प्रभावित होने के साथ-साथ यह क्षेत्र बागवानी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सड़कों का बेहतर नेटवर्क किसानों और बागवानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण समृद्धि की आधारशिला हैं। क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक वर्ष के भीतर इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में कई वर्षों से लंबित करीब 30 भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर : शिक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए शिक्षा, सड़क और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के 150 से अधिक विद्यालयों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप परिवर्तित किया गया है। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं।

रोहित ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का उल्लेख करते हुए सरकारी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश : शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को गति देने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं और शिकायतें भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया।

शिमला के प्रमुख बाजार शहर से बाहर होंगे स्थानांतरित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को कम करने के लिए सब्जी मंडी, गंज मंडी, मीट मार्केट और ऑटोमोबाइल मार्केट को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। इन बाजारों को एक ही स्थान पर विकसित करने का प्रस्ताव है। बाजारों को स्थापित करने के लिए प्रशासन ने मल्याणा और शोघी में जमीन चिह्नित की है। दोनों स्थानों की उपलब्ध जमीन और अन्य सुविधाओं का आकलन किया जाएगा।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate Tenders on form MW-4, MW-7 are invited by the Assistant Engineer, Zila Parishad Solan for the below mentioned works from the approved and eligible manufacturers company/firm registered so as to reach in this office on or before 21.10.2026 up to 11.30 AM and will be opened on same day at 3.00 pm in the presence of intending companies/firms Or their representative. The tender form can be had from this office against the cash payment(non refundable) up to 10.00 AM on 21.10.2026. The earnest money in the shape of fixed deposit of the scheduled bank duly pledged in favour of Assistant Engineer, Zila Parishad Solan. The Assistant Engineer, Zila Parishad Solan reserves the right to accept or reject any or all the tender or to drop the proposal of the tender without assigning any reason.

SR. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of tender form	Time for completion
1	C/o Link Road Jatoli Garog Road to Hem Chand House.	497500.00	12500.00	350.00	One month

Terms & Conditions: **1.** The tender document shall only be issued to the Registered contractors who will produce the photocopy of the authorization. **2.** In case of holiday on the day of opening of tender, the same will be opened on the next working day on the same time and venue. **3.** Other term &condition as per DNIT and can be seen in the office of the Distt. Development officer Solan on the working day. **4.** The firm are requested to insert the items rates of each items in words as well as in figures failing/considered in any case. **5.** No tender form will be issued to the defaulter contractor by any of these HPPWD/IPH/CPWD tenders/conditional HIMUDA/MC department which the DDO reserve the right to accept/reject any or all the tender or tenders by fax shall not be entertained **6.** The contractor must give the copy of GST/CST No.TIN number & photocopy of PAN No. allotted with their application at the time of applying for the tender document.

-sd-Assistant Engineer, Zila Parishad Solan District Solan, (H.P.)

न्यूज ब्रीफ

हिमाचल अकैडमिक स्कूल समूहगान फर्स्ट



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। हिमाचल अकैडमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने ब्लॉक स्तरीय अंडर-14 छात्र प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने समूहगान में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि लोकगीत प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी और उत्साह का माहौल है। विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और संगीत के प्रति रुचि की सराहना की जा रही है। विद्यालय के लिए यह उपलब्धि गर्व का विषय है। विद्यार्थियों के बेहतरीन प्रदर्शन ने सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी प्रतिभा और समर्पण को प्रदर्शित किया।

छाती के एक्स-रे, बीपी व शुगर निःशुल्क जांचा

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। ग्राम पंचायत कुंहर व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पंचायत घर कुंहर में फ्री स्वास्थ्य जांच एवं एक्स-रे शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छाती के एक्स-रे, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच निःशुल्क की। पंचायत प्रधान अमर सिंह ठाकुर और उपप्रधान जुगल किशोर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपप्रधान ने कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीणों को घर-द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं और बीमारियों की समय पर पहचान संभव होती है।

सुधीर शर्मा राजनीतिक टूरिस्ट, विकास पर सवाल उठाने से पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएं: पुनीत मल्ली

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पुनीत मल्ली ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीतिक टूरिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के विकास कार्यों पर सवाल उठाने से पहले सुधीर शर्मा अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। मल्ली ने कहा कि धर्मशाला में युवाओं के रोजगार, आईटी पार्क और पर्यटन सुविधाओं को लेकर भाजपा विधायक अपने कार्यकाल के ठोस परिणाम बताएं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तथ्यों के बजाय आरोपों की राजनीति कर रही है।

धर्मशाला में 33.78 करोड़ के आइस स्केटिंग रिंक से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: देवेंद्र सिंह जग्गी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। पूर्व महापौर देवेंद्र सिंह जग्गी ने सकोह में 33.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इंडोर आइस एवं रोलर स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के अवसर मिलने के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। परिसर में जिम, कैफे, बिलियर्ड्स रूम और 250 वाहनों की पार्किंग सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जग्गी ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

नवनियुक्त कार्यकारी अधिकारी संजय शर्मा ने एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा से की भेंट

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। नवनियुक्त नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संजय शर्मा ने पदभार ग्रहण करने से पूर्व एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अजय वर्मा ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अजय वर्मा ने उम्मीद जताई कि संजय शर्मा के अनुभव और कार्यकुशलता से नगर परिषद के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन और नगर परिषद के बेहतर समन्वय से जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

घट्टा टोल बैरियर पर ₹25 की पुरानी दर बहाल करने के आदेश

खस्ताहाल सड़क और बढ़ी वसूली पर उपभोक्ता आयोग सख्त

सन्नी महाजन, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। खस्ताहाल सड़क और बढ़ी हुई टोल वसूली को लेकर घट्टा टोल बैरियर के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को झटका दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए टोल बैरियर पर 30 सितंबर 2026 से पहले लागू 25 रुपए की पुरानी दर से वसूली करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बढ़ी हुई दरों पर तत्काल रोक लगा दी है।

यह मामला सनी कौंडल और उनके तीन साथियों की शिकायत पर सामने आया। शिकायतकर्ताओं ने सड़क की खराब स्थिति और टोल दरों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे। उनके वकील अभिषेक पाधा ने आयोग के समक्ष दलील दी कि सड़क की चारों लेन पूरी तरह चालू नहीं हैं और लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद घट्टा टोल बैरियर पर बढ़ी हुई दरों से वसूली की जा रही है। शिकायत में बालूग्लोआ की ओर सड़क का हिस्सा बंद होने और देहरा जाने वाले यात्रियों के पास वैकल्पिक मार्ग की कमी का मुद्दा भी उठाया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की पीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। आयोग ने सड़क सुविधाओं में कमी और टोल वसूली से जुड़े पहलुओं पर विचार करते हुए बढ़ी हुई दरों पर रोक लगाने का आदेश दिया। शिकायत के अनुसार, बैरियर पर सिंगल ट्रिप के लिए 65 रुपये और 24 घंटे के लिए 100 रुपये वसूले जा रहे थे।

आयोग ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि घट्टा टोल बैरियर पर पुरानी 25 रुपये की दर लागू की जाए। साथ ही आदेश का पालन कर उसी दिन शाम चार बजे तक ईमेल के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया। आयोग ने संबंधित पक्षों से यह भी जवाब मांगा है कि अंतरिम आदेश को आगे स्थायी क्यों न किया जाए।

मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को

इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर 2026 को निर्धारित की गई है। आयोग के आदेश से टोल दरों को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। हालांकि, आदेश के अनुपालन और आगे की कार्यवाही पर अंतिम स्थिति अगली सुनवाई में स्पष्ट होगी।

सजाओपिपलू-अवाहदेवी सड़क 23 तक रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। धर्मपुर उपमंडल में सजाओपिपलू-अवाहदेवी सड़क पर निर्माण कार्य के चलते 18 से 23 अक्टूबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। प्रशासन ने यह निर्णय गेहरा जोढण से लोंगणी की ओर जाने वाले मार्ग पर किलोमीटर 0/00 से 2/00 तक सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट निर्माण कार्य के मद्देनजर लिया है।

उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में यातायात को टॉरी नाला-भेड़ी, गेहरा-जोड़ण भेरी-पाड़छू तथा सजाओपिपलू-पाड़छू सड़क मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने के लिए सूचना पट्ट लगाने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

नादौन के ब्वॉयज-गर्ल्स स्कूल का मर्जर रद्द, दोनों सह-शिक्षा के रूप में चलेंगे

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल सरकार ने अहम फैसला लेते हुए नादौन शहर के दो सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विलय रद्द कर दिया है, लेकिन दोनों स्कूल सह-शिक्षा के रूप में संचालित होंगे। स्कूलों के नाम में आंशिक बदलाव किया गया है। पुराना ब्वॉयज स्कूल सीबीएसई होगा, जबकि गर्ल्स स्कूल में एचपी बोर्ड की पढ़ाई होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पूर्व में पीएम श्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट (ब्वॉयज) सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन और पीएम श्री उत्कर्ष गवर्नमेंट (गर्ल्स) सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन को एक ही सह-शिक्षा स्कूल के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया था। नई अधिसूचना के अनुसार अब दोनों विद्यालय स्वतंत्र रूप से सह-शिक्षा स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। इसके तहत दोनों स्कूलों के नाम और बोर्ड संबद्धता भी निर्धारित की गई है।

पीएम श्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन लीड स्कूल होगा। इस विद्यालय का सीबीएसई से संबद्ध रहेगा। पीएम श्री उत्कर्ष गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपी बोर्ड) से संबद्ध रहेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विलय संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए दोनों विद्यालयों को अलग-अलग संचालित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में लिए गए निर्णय में स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों की मांग पर संशोधन हुआ है। स्थानीय लोगों ने सीएम सुक्खू के समक्ष यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।

◆ **पुराना ब्वॉयज स्कूल सीबीएसई व गर्ल्स स्कूल में होगी एचपी बोर्ड की पढ़ाई**

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद, जिप सदस्य रविंद्र गद्दी, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष शम्मी सोनी, पूर्व निदेशक मोती जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता रमणीक परमार, नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रीना कुमारी, संतोष संधू, कमल कम्मी, डिंपल कटोच, मोंटी संधू, राजिंद्र बबलू इत्यादि ने सरकार के फैसले का स्वागत और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है।

एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर लौटे सावन बरवाल का किया स्वागत



जितेंद्र कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। जोगिंद्रनगर। जापान के नागोया में आयोजित एशियन गेम्स में पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले जोगिंद्रनगर के धावक सावन बरवाल का मंडी जिले के प्रवेश द्वार घट्टा में जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें बैंड-बाजे के साथ गांव रड़ा भखेड़ ले जाया गया, जहां नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने सावन को सम्मानित करते हुए कहा कि साधारण परिवार से संबंध रखने वाले इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि चालक के बेटे की यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सावन के कोच राजेंद्र और गोपाल ठाकुर को भी बधाई दी। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सावन को ढाई करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

सावन बरवाल ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी सफलता का श्रेय कोचों के मार्गदर्शन को दिया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 44 साल बाद भारत को इस स्पर्धा में पदक दिलाया। अप्रैल 2026 में उन्होंने शटर डैम मैराथन में 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा था।

धर्मशाला में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न डिजिटल सुशासन पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। ई-गवर्नेंस सुधारों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार, डेटा एनालिटिक्स और नागरिक-केंद्रित सुशासन को मजबूत बनाने पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिक रोहित त्यागी ने साइबर सुरक्षा और डीएनएस फिल्टरिंग सेवा की जानकारी दी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अजय कुमार ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, जबकि रक्षा मंत्रालय के कैप्टन रितेश वाही ने क्वांटम-सुरक्षित वीपीएन तकनीक पर प्रस्तुति दी।

एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा ने सेब खरीद प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से हुई प्रगति साझा की। वहीं, विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने डिजिटल शासन की सफल पहलें प्रस्तुत कीं। समापन सत्र में प्रशासनिक सुधार सचिव ए. शैनामोल ने कहा कि सम्मेलन से विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

हरियाणा में हिमाचली खिलाड़ियों का दबदबा

राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में दो स्वर्ण सहित 14 पदक किए हासिल



भारतेन्दु संवाददाता, रतिया (हरियाणा)। गुरु नानक स्पोर्ट्स अकादमी, रतिया में 15 से 17 अक्तूबर तक आयोजित 10वीं राष्ट्रीय सब-जूनियर एवं जूनियर गतका स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दो स्वर्ण, पांच रजत और सात कांस्य सहित कुल 14 पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया।

चैंपियनशिप में लड़कों और लड़कियों ने विभिन्न आयु वर्गों की स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश के खेल जगत में खुशी का माहौल है।

लड़कों के वर्ग में अंडर-11 इंडिविजुअल डेमो में जसमीत सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-14 वर्ग में परमिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फरी सोठी इंडिविजुअल स्पर्धा में कर्मवीर ने कांस्य और सिंगल सोठी इंडिविजुअल में एकमप्रीत ने रजत पदक प्राप्त किया।

अंडर-17 फरी सोठी इंडिविजुअल में राजवीर और सिंगल सोठी स्पर्धा में सोनू सिंह ने रजत पदक जीते। वहीं, अंडर-14 सिंगल सोठी टीम स्पर्धा में हिमाचल की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कियों के वर्ग में अंडर-11 इंडिविजुअल डेमो और सिंगल सोठी टीम स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल हुए। अंडर-14 इंडिविजुअल डेमो में कांस्य, इंडिविजुअल फरी सोठी और टीम डेमो में रजत पदक मिले। अंडर-17 इंडिविजुअल डेमो और टीम डेमो में भी हिमाचल की खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की।

हिमाचल प्रदेश गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन संजय पराशर, महासचिव सुनीता देवी, उपाध्यक्ष शुभकरण सिंह और कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को बधाई दी। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि हिमाचल के खिलाड़ी भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे।















चन्नी ने पंजाब में अवैध खनन पर मान सरकार को घेरा

खनन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, चन्नी ने प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब में रेत खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में रात के समय भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर रेत का खनन किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों को राज्य का 'सफेद सोना' बताते हुए आरोप लगाया कि इसकी लूट हो रही है। चन्नी ने पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने खनन से हर साल 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई करने का वादा किया था। हालांकि, उनके आरोप के मुताबिक, सरकार इस क्षेत्र से 20 करोड़ रुपये भी जुटाने में सफल नहीं रही। चन्नी ने दावा किया कि खनन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा नेताओं की जेब में जा रहा है। उन्होंने सरकार से खनन संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की।

चन्नी ने 'मिशन चिट्टा सोना' के तहत रूपनगर जिले के नूरपुरबेदी ब्लॉक में कथित अवैध खनन का मामला उठाया। उनके अनुसार, वह बीती रात करीब 12 बजे कांग्रेस नेता बरिंदर ढिल्लों और अपने समर्थकों के साथ टिप्पर में सवार होकर सैदपुर और बेईहारा गांवों के नजदीक सतलुज नदी के किनारे पहुंचे। चन्नी ने दावा किया कि वहां एक दर्जन से अधिक पोकलेन मशीनें, रेत और पत्थरों से भरे टिप्पर तथा कई कर्मचारी मौजूद थे।

पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक, उनके मौके पर पहुंचने के बाद कुछ लोग अपने वाहन छोड़कर भाग गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थीं और वहां संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले वायरलेस सेट भी मिले। चन्नी ने इन परिस्थितियों को कथित अवैध खनन से जोड़ते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

चन्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने मौके से रूपनगर के उपायुक्त को फोन कर अधिकारियों की टीम भेजने का आग्रह किया था। इसके बावजूद काफी समय बीतने पर भी कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। उन्होंने इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी और समय पर कार्रवाई जरूरी है।

उन्होंने मांग की कि सतलुज नदी के किनारे कथित अवैध खनन की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि इसमें किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

चन्नी के दौरे के बाद खनन विभाग ने कार्रवाई की। विभाग की शिकायत पर नूरपुरबेदी पुलिस ने पास के सवाड़ा गांव में खान एवं खनिज अधिनियम के तहत अज्ञात जमीन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि, मामले में आरोपों की जांच और संबंधित लोगों की भूमिका का निर्धारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

इस घटनाक्रम ने पंजाब में रेत खनन और उससे होने वाली आय को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। चन्नी ने जहां सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित विभाग की जांच पर निर्भर करेगी।

लाखों के जुर्माने के विरोध में पंजाब में आधार सेवाएं ठप, ऑपरेटरों की हड़ताल जारी

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर



पंजाब में सर्विस सेंटर ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण आधार पंजीकरण और टोकन प्रणाली से जुड़े काम ठप हो गए हैं। ऑपरेटरों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाने और वेतन से किश्तों में इसकी वसूली किए जाने के विरोध में सर्विस सेंटर मुलाजिम यूनियन पंजाब ने 13 अक्टूबर से काम बंद करने का आह्वान किया था। यूनियन का कहना है कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सेवाएं प्रभावित होने से आधार बनवाने और उसमें बदलाव करवाने पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिहाड़ी मजदूरों, नौकरीपेशा लोगों और बुजुर्गों को बिना काम करवाए लौटना पड़ रहा है।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलजिंदर सिंह माझा और महासचिव गुरसेवक सिंह चहल ने 12 अक्टूबर को प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक को पत्र भेजा था। इसकी प्रति मोहाली के उपायुक्त को भी भेजी गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने जुर्मानों की सूची जारी कर कर्मचारियों के वेतन से वसूली के लिए किश्तें निर्धारित कर दी हैं। यूनियन के मुताबिक, पिछली हड़ताल के दौरान विभाग और कंपनी के बीच जुर्माना नहीं लगाने पर सहमति बनी थी, इसके बावजूद दोबारा कटौती की जा रही है।

यूनियन ने सवाल उठाया है कि किस तारीख को, किस टोकन पर और किस ऑपरेटर की गलती के कारण जुर्माना लगाया गया, इसका स्पष्ट विवरण क्यों नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने बिजली कटौती, सर्वर की खराबी और अन्य तकनीकी समस्याओं की भूमिका पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि वेतन से इस तरह की वसूली के लिए उन्होंने कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया था। लोहगढ़ सेवा केंद्र के ऑपरेटर गुरजंट सिंह के अनुसार, कुछ कर्मचारियों पर डेढ़ लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

न्यूज ब्रीफ

शाहकोट में पराली जलाने पर सख्ती, दो मामलों में किसानों पर कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, शाहकोट। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए शाहकोट प्रशासन और पुलिस ने पांच गांवों में जागरूकता अभियान चलाया। एसडीएम आदित्य गुप्ता और डीएसपी सरवन सिंह बल्ल के नेतृत्व में अधिकारियों ने नंगल अंबियां, रौंता, मंडाला, कोठा और चक्क गदाईपुर का दौरा कर किसानों को पराली न जलाने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित होती है। सरपंचों, पंचों और नंबरदारों को गांवों में मुनादी करवाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने बताया कि तहसील शाहकोट में पराली जलाने के दो मामले सामने आए हैं। संबंधित जमीन मालिकों पर जुर्माना लगाने, जमाबंदी में लाल प्रविष्टि करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। किसानों को मशीनरी या अन्य सहायता के लिए कृषि विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई।

सर्वर ठप, रजिस्ट्री ठप: जालंधर में 130 आवेदकों के अटके संपत्ति दस्तावेज़

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। पंजाब सरकार का ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुक्रवार को सर्वर ठप होने से लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। सब रजिस्ट्रार जालंधर-1 और जालंधर-2 कार्यालयों में ऑनलाइन दस्तावेजों की मंजूरी का काम करीब चार घंटे प्रभावित रहा। सुबह 11 बजे सर्वर बंद होने के बाद दोपहर तीन बजे कामकाज बहाल हुआ। इस दौरान रजिस्ट्री, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों की मंजूरी के लिए पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ा। जालंधर-1 कार्यालय में 169 अपॉइंटमेंट में से 107 दस्तावेजों को मंजूरी मिली, जबकि 62 आवेदक प्रभावित हुए। वहीं, जालंधर-2 में 129 आवेदनों में से 61 को मंजूरी मिली और 68 आवेदकों का काम अटक गया। सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण प्रभावित लोगों को सोमवार तक इंतजार करना पड़ सकता है। अधिकारियों की अन्य ड्यूटी पर तैनाती से भी काम प्रभावित हुआ। समाजसेवी एसपी सिंह ढींगरा ने सवाल उठाया कि तकनीकी खराबी का खामियाजा जनता क्यों भुगते। उन्होंने मांग की कि सर्वर बंद होने पर प्रभावित आवेदकों को दोबारा अपॉइंटमेंट लिए बिना दस्तावेजों की मंजूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

जालंधर के चौराहों पर भीख मांगने वालों से रोजाना हजारों रुपए वसूली का दावा

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। शहर के चौराहों पर भीख मांगने वाले लोगों के पीछे कथित वसूली नेटवर्क सक्रिय होने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में महिलाओं के कपड़े पहनकर पैसे मांग रहे व्यक्ति ने दावा किया कि कपूरथला चौक पर भीख मांगने वाले चार लोगों से रोजाना एक-एक हजार रुपये लिए जाते हैं। वीडियो बनाने वाले युवक से बातचीत में व्यक्ति ने बताया कि पहले रोजाना 500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब यह रकम बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। उसके मुताबिक, शहर के अलग-अलग चौराहों पर पैसे मांगने वालों के स्थान तय हैं और हर चौक से वसूली की जाती है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी को जबरन भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं।

गुरदासपुर डीसी कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के दावे से हड़कंप

भारतेन्दु संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर ग्रेनेड हमले का दावा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। हालांकि, पुलिस ने वीडियो में किए जा रहे दावों को खारिज किया है। जानकारी के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके मद्देनजर डीसी कार्यालय के बाहर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने आसपास के क्षेत्र की जांच की, ताकि किसी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी का पता लगाया जा सके।

पंजाब में नशे पर सियासी संग्राम तेज, परगट सिंह ने अमित शाह की जवाबदेही पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर



पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नशे का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। प्रदेश में नशाखोरी की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। वहीं, भाजपा के पंजाब प्रभारी नितिन नवीन ने राज्य सरकार को घेरते हुए ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने सवाल उठाया कि यदि पंजाब में नशे की समस्या इतनी गंभीर है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी भयावह स्थिति का अहसास अब क्यों हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए। परगट सिंह का कहना है कि पिछले 13 वर्षों से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले नेतृत्व को पंजाब में नशे के संकट की गंभीरता को लेकर जवाब देना चाहिए।

पंजाब में नशाखोरी लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस समस्या को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। चुनावी माहौल में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज होने से राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

दूसरी ओर, भाजपा के पंजाब प्रभारी नितिन नवीन ने राज्य में नशे की समस्या को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा का रुख है कि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस जहां केंद्र की भूमिका पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा राज्य सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा राजनीतिक बहस में प्रमुख स्थान हासिल करता दिख रहा है।

भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से पहुंची जाली करंसी बरामद, पुलिस ने तेज की जांच

भारतेन्दु संवाददाता, तरनतारन



भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन के जरिए जाली भारतीय करंसी भेजे जाने का मामला सामने आया है। तरनतारन जिले में थाना खालड़ा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सीमावर्ती गांव कलसियां के नजदीक से 3 लाख 98 हजार 500 रुपये की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि जाली करंसी कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरिंदर लांबा ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त के दौरान एंटी ड्रोन प्रणाली के संचालक ने गांव कलसियां के पास ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने इलाके में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे पीले रंग का एक संदिग्ध पैकेट मिला। सुरक्षा कर्मियों ने पैकेट की जांच की तो उसमें से 3,98,500 रुपये की जाली भारतीय करंसी बरामद हुई। इसके बाद नकली मुद्रा को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार, ड्रोन की गतिविधि का पता चलने के बाद तत्काल तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान यह बरामदगी हुई। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ड्रोन किस दिशा से आया था और पैकेट को किसने वहां गिराया।

एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि थाना खालड़ा में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद जाली करंसी के स्रोत का पता लगाने के साथ-साथ इस मामले से जुड़े संभावित लोगों की पहचान करने में जुटी है।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि बरामद मुद्रा किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है।

पोस्टिंग, टेंडर और जमीन सौदों की जांच में सीबीआई ने तेज की कार्रवाई, छह नामजद

भ्रष्टाचार जांच में भगवंत मान के ओएसडी से पूछताछ सीबीआई ने सोमवार को दोबारा फिर बुलाया

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर संबंधी मामलों की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने पेश हुए। करीब साढ़े पांच घंटे चली पूछताछ के दौरान उनसे लगभग 40 सवाल किए गए। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार दोपहर दो बजे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके साथ अधिवक्ता जीपीएस घुम्मन भी मौजूद रहे।

वकील के अनुसार, राजबीर घुम्मन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जांच में सहयोग करने पहुंचे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है। हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर को सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने छह अक्टूबर को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिकी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने उस चरण में आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कठोर कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम निर्देश दिया था। अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने को कहा था।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई और अगस्त 2026 में पंजाब के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच शुरू की।

सीबीआई की 251 पन्नों की एफआईआर में छह लोगों को नामजद किया गया है। इनमें राजबीर सिंह घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और राइस शेलर कारोबारी राजदीप सिंह नागरा शामिल हैं। प्राथमिकी में वर्ष 2023 से 2026 के बीच की कथित गतिविधियों की जांच का उल्लेख है।

एफआईआर के अनुसार, जांच के दायरे में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्रवाई, नीतिगत फैसले, सरकारी टेंडर, लाइसेंस, चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), संपत्ति विवाद और राजस्व मामलों में कथित लेन-देन शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि नितिन गोहल सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और राजबीर घुम्मन के बीच कथित बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था। एजेंसी ने वाट्सऐप चैट और अन्य डिजिटल सामग्री मिलने का दावा भी किया है।

मोहाली के इमिग्रेशन सलाहकार को बदनाम करने के आरोप में 35 अकाउंट पर एफआईआर दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मोहाली के एक इमिग्रेशन सलाहकार और उससे जुड़े कारोबारी समूह को इंटरनेट मीडिया पर कथित तौर पर बदनाम करने के मामले में पंजाब पुलिस ने 35 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन अकाउंट में पंजाब और कनाडा से जुड़े कुछ पंजाबी पत्रकारों तथा इमिग्रेशन सलाहकारों के अकाउंट भी शामिल बताए गए हैं। आरोप है कि इनके माध्यम से बिना सत्यापन वाली सामग्री प्रसारित कर कंपनी को कनाडा में कथित धोखाधड़ी से जोड़ा गया।

संबंधित कारोबारी समूह शैक्षणिक संस्थान चलाने के साथ मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़ा है। इस मामले में 13 अक्टूबर को एसएएस नगर के सेक्टर-79 स्थित साइबर क्राइम थाने में एफआईआर संख्या 29 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया है।

जीबी रियल्टी ग्रुप की ओर से अधिवक्ता पारस शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, अज्ञात व्यक्तियों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य इंटरनेट मीडिया मंचों पर कंपनी तथा उसके प्रबंध निदेशक के संबंध में कथित तौर पर भ्रामक सामग्री प्रसारित की। शिकायतकर्ता ने संबंधित पोस्ट और अकाउंट के लिंक पुलिस को सौंपते हुए सामग्री हटाने तथा अकाउंट बंद करने की मांग की है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कनाडा के ओंटारियो प्रांत में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने वाली योजना में संभावित अनियमितताओं की जांच चल रही है। प्रांतीय सरकार ने प्रारंभिक आडिट में सामने आई चिंताओं के बाद मामला ओंटारियो प्रांतीय पुलिस को भेजा है।

◆ कनाडा में धोखाधड़ी से जोड़ने पर विवाद, मोहाली में 35 सोशल मीडिया अकाउंट पर केस

विकास योजनाओं के लिए पंजाब सरकार 800 करोड़ रुपए का लेगी कर्ज

विकास योजनाओं और पूंजीगत खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार जारी करेगी 17 वर्षीय बांड

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब सरकार विकास योजनाओं और पूंजीगत खर्चों को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने जा रही है। इसके लिए सरकार 7.65 प्रतिशत सालाना ब्याज दर वाले पंजाब एसजीएस 2043 सरकारी बांड दोबारा जारी करेगी। इन बांड की अवधि 17 साल होगी और इनकी परिपक्वता तिथि 12 अगस्त 2043 निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इन बांड की नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को करेगा।

पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी, जिसे 16 अक्टूबर को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के अनुसार, 800 करोड़ रुपये के ये बांड 12 अगस्त 2026 को जारी किए गए 7.65 प्रतिशत ब्याज दर वाले पंजाब एसजीएस 2043 बांड को दोबारा जारी करने के तहत बेचे जाएंगे। सरकार इस कर्ज से चल रही पूंजीगत योजनाओं और अन्य विकास कार्यों के खर्च का एक हिस्सा पूरा करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार की सहमति भी प्राप्त की गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाले निवेशक 19 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक और गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाले सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक आरबीआई के ई-कुबेर इलेक्ट्रॉनिक मंच पर अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे।

नीलामी के परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे और इन्हें रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। सफल बोलीदाताओं को 21 अक्टूबर 2026 को बैंकिंग समय समाप्त होने से पहले भुगतान करना होगा। भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार नकद, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट अथवा संबंधित बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकेगा।

नीलामी में कुल निर्धारित राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा पात्र व्यक्तियों और संस्थानों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था के तहत आवंटित किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में एक बोलीदाता के लिए अधिकतम सीमा अधिसूचित राशि का एक प्रतिशत निर्धारित की गई है। इससे पात्र निवेशकों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में सीधे भाग लिए बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर मिलेगा।

इन बांड पर 7.65 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा। ब्याज की गणना 12 अगस्त 2026 की मूल जारी तिथि से बांड के अंकित मूल्य के आधार पर की जाएगी। निवेशकों को ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी और 12 अगस्त को दो किस्तों में किया जाएगा। बांड की अवधि 12 अगस्त 2026 से शुरू होकर 12 अगस्त 2043 तक रहेगी। परिपक्वता पर सरकार निवेशकों को अंकित मूल्य के बराबर मूलधन लौटाएगी।

ये सरकारी प्रतिभूतियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगी। साथ ही, इनका इस्तेमाल रेडी फॉरवर्ड लेनदेन के तहत भी किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कर्ज से विकास योजनाओं और पूंजीगत व्यय से जुड़ी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

चंडीगढ़ के मास्टर प्लान से छेड़छाड़, स्लिप रोड हटाने से बढ़ा जाम, प्लाजा में कारों का कब्जा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



देश के सबसे सुनियोजित शहरों में शामिल चंडीगढ़ की मूल योजना और विशिष्ट पहचान पर अतिक्रमण तथा गलत यातायात प्रबंधन के कारण सवाल उठने लगे हैं। शहर के हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले सेक्टर-17 प्लाजा में पैदल चलने के लिए बनाए गए रास्तों पर कारों का कब्जा है। वहीं, सेक्टर-7 में स्लिप रोड हटाकर पार्किंग बनाने से मध्य मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इन बदलावों को लेकर शहर की नियोजित व्यवस्था और मास्टर प्लान के पालन पर चिंता जताई जा रही है।

सेक्टर-17 प्लाजा को इस तरह विकसित किया गया था कि लोग बिना वाहनों के व्यवधान के पैदल घूम सकें और खरीदारी कर सकें। यहां वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन कार्यालय के बाहर प्लाजा के बड़े हिस्से में कारें खड़ी की जा रही हैं। प्लाजा के दूसरे हिस्सों में भी कई स्थानों पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं। इससे पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित जगह पर अतिक्रमण बढ़ रहा है और प्लाजा की मूल अवधारणा प्रभावित हो रही है।

दूसरी ओर, शहर के प्रमुख मार्गों के साथ बनाई गई स्लिप रोड को भी पार्किंग के लिए हटाया जाने लगा है। स्लिप रोड का उद्देश्य मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव कम करना, सेक्टरों में वाहनों के प्रवेश और निकास को सुगम बनाना तथा चौराहों पर यातायात संचालन को व्यवस्थित रखना है। सेक्टर-7 के ब्लॉक सी में कारों की पार्किंग बढ़ाने के लिए स्लिप रोड को खत्म कर उसे पार्किंग में मिला दिया गया। इसका असर अब मध्य मार्ग पर दिखाई दे रहा है। सेक्टर-7 में प्रवेश करने वाले वाहनों को पार्किंग के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या बढ़ रही है।

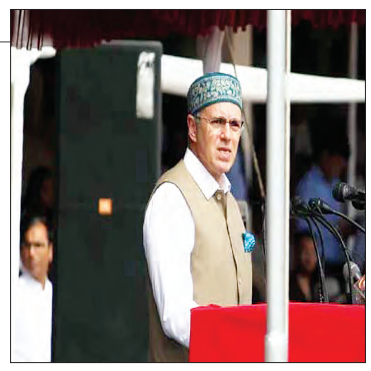
ली कार्बूजिए सेंटर की पूर्व निदेशक दीपिका गांधी ने कहा कि सड़क पर चलने का पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। यदि हर जगह वाहनों की पार्किंग होगी, तो पैदल चलने वालों के लिए जगह कहां बचेगी। उन्होंने कहा कि सेक्टर-17 प्लाजा जैसी व्यवस्था को खराब नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्लिप रोड हटाने से मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित हो सकता है और हादसों का खतरा बढ़ सकता है। किसी भी बदलाव से पहले चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का अध्ययन और प्रभाव का आकलन जरूरी है, ताकि शहर की नियोजित संरचना और यातायात व्यवस्था सुरक्षित रह सके।

जम्मू-कश्मीर में चक्रीय अर्थव्यवस्था नीति लागू

दस वर्षों में 3,548 करोड़ रुपए होंगे खर्च, कचरे से संसाधन और रोजगार सृजन पर जोर

भारतेंदु संवाददाता, लेह



जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नव अधिसूचित जम्मू-कश्मीर चक्रीय अर्थव्यवस्था नीति-2026 को संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, हरित विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में कचरे की मात्रा कम करने, उपयोगी संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करने और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और विभिन्न प्रकार की बस्तियों की जरूरतों के अनुरूप ठोस कचरा प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति तथा अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की व्यवस्था विकसित करना है। इसके लिए चक्रीय, चक्रीय प्लस और चक्रीय प्लस प्लस नाम से तीन स्तरीय प्रणाली प्रस्तावित की गई है। इसके तहत स्थानीय निकायों की क्षमता और जरूरतों के अनुसार कचरा प्रबंधन की योजनाएं तैयार की जाएंगी। नीति में कचरे को केवल निपटाने योग्य सामग्री मानने के बजाय उससे उपयोगी संसाधन तैयार करने पर जोर दिया गया है।

नीति के तहत नगर निगमों से निकलने वाले ठोस कचरे, खाद्य एवं गीले कचरे, पर्यटन गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट, बागवानी और कृषि अवशेष, पैकेजिंग सामग्री, निर्माण एवं विध्वंस मलबे, इलेक्ट्रानिक कचरे तथा अपशिष्ट जल को शामिल किया गया है। छोटे और दूरदराज के क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्यवर्ती क्षेत्रों में कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए केंद्र आधारित व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

◆कचरे से संसाधन और रोजगार बढ़ाने पर जोर

वहीं, जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहरी केंद्रों में उन्नत चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणालियां स्थापित करने पर जोर रहेगा। नीति में मरम्मत, नवीनीकरण और पुन: उपयोग के माध्यम से वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है। ऊन और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि सामग्री की बर्बादी कम हो और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।

जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष के लिए संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र और क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें शहरी कचरे से उपयोगी सामग्री प्राप्त करना, सेब एवं बागवानी अवशेषों का उपयोग, पर्यटन स्थलों से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन और हस्तशिल्प से संबंधित सामग्री का पुन: उपयोग शामिल है। इन व्यवस्थाओं के जरिए कचरा प्रबंधन को स्थानीय आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार सृजन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

दस वर्षों के लिए 3,548.7 करोड़ का प्रावधान

नीति में अगले दस वर्षों के लिए 3,548.7 करोड़ रुपये का सांकेतिक वित्तीय प्रावधान रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था, उपयोगकर्ता शुल्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे माध्यमों से वित्त जुटाने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन से जुड़े दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे का विकास करना और नियमित सरकारी सहायता पर निर्भरता कम करना है। नीति का प्रमुख लक्ष्य स्रोत स्तर पर कचरे को अलग करना, पुनर्चक्रण व्यवस्था मजबूत बनाना और भराव स्थलों पर पहुंचने वाले कचरे की मात्रा घटाना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक सामग्री पुनर्प्राप्ति हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से संसाधनों की बर्बादी कम होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

चिनाब पुल से कश्मीर का रेल संपर्क मजबूत

हर मौसम में रेल से जुड़ेगी घाटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

◆बर्फबारी और भूस्खलन के बीच भी माल ढुलाई व यात्री आवाजाही सुगम

कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल सहित इस रेल परियोजना के पूरा होने से घाटी और राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छह जून 2025 को इस रेल लिंक का उद्घाटन किया था। इस परियोजना से पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेल यात्रा संभव हुई है। इससे खराब मौसम, भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित होने की स्थिति में परिवहन के वैकल्पिक साधन को मजबूती मिलेगी। रेल संपर्क बेहतर होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा

इस रेल मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित यात्री और मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, श्रीनगर और जम्मू के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। रेल सेवा से कश्मीरी सेब सहित अन्य कृषि उत्पादों को देश के बाजारों तक पहुंचाने में लगने वाला समय घटने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेल मार्ग से 20 हजार टन से अधिक सेब देश के विभिन्न बाजारों तक भेजे जा चुके हैं।

रियासी जिले में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना रेलवे पुल करीब 1,315 मीटर लंबा है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके निर्माण पर लगभग 580 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुल को मजबूत संरचना और विशेष तकनीकी मानकों के साथ तैयार किया गया है। यह भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है और तेज हवाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेल लिंक के चालू होने से कश्मीर घाटी तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का विकल्प उपलब्ध हुआ है। इससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने और परिवहन व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिल सकती है।

कुपवाड़ा में एलओसी पर मुठभेड़ में दो आतंकियों के खात्मे की आशंका

भारतेंदु संवाददाता, कुपवाड़ा



◆केरन सेक्टर के जुमागुंड में तड़के गोलीबारी, इलाके में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में सुरक्षाबलों और संदिग्ध आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। आखिरी सूचना मिलने तक अभियान जारी था और सुरक्षाबल पूरे इलाके में स्थिति पर नजर बनाए हुए थे।

अधिकारियों के अनुसार, शनिवार तड़के केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने सतर्कता बरतते हुए इलाके में कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 3:30 बजे शुरू हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों की कार्रवाई के दौरान दो आतंकियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षाबल आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी अन्य संदिग्ध की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। अभियान पूरा होने के बाद ही मुठभेड़ और आतंकियों के हताहत होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी है और आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

सरकारी नौकरी छोड़ कैंसर पीड़ित बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटीं सुरुचि शर्मा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के तालाब तिल्लो की रहने वाली सुरुचि शर्मा ने कैंसर पीड़ित बच्चों की सेवा के लिए सरकारी शिक्षिका की नौकरी तक छोड़ दी। उनके समर्पित प्रयासों और चिकित्सकों के साथ समन्वय से कई बच्चों को उपचार जारी रखने में मदद मिली है। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में कैंसर का इलाज करवाने आने वाले बच्चों और उनके परिवारों को वह लगातार सहायता उपलब्ध करवा रही हैं। जम्मू विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर सुरुचि वर्ष 2016 में गैर सरकारी संगठन कैनकिड्स किड्सकैन से जुड़ी थीं। वर्ष 2018 में सरकारी शिक्षिका की नौकरी मिलने के बावजूद उन्होंने बच्चों की सेवा को प्राथमिकता दी। वह जरूरतमंद परिवारों को जांच, दवाइयों, परिवहन, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और शिक्षा संबंधी सहायता दिलाने में मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही बच्चों और उनके परिजनों को मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग भी देती हैं। नियमित संपर्क और फालोअप के जरिए वह सुनिश्चित करती हैं कि आर्थिक या अन्य परेशानियों के कारण बच्चों का उपचार बीच में न छूटे। उनके प्रयासों से बच्चों के इलाज छोड़ने की दर 24 प्रतिशत से घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई है।

जम्मू-श्रीनगर में यातायात सुधार की तैयारी, पार्किंग और सुरक्षा पर जोर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



स्कूल बसों का सुरक्षा ऑडिट, ई-चालान और आधुनिक निगरानी प्रणाली से यातायात नियमों का पालन होगा सुनिश्चित

जम्मू और श्रीनगर में बढ़ती यातायात समस्या, जाम और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यातायात प्रबंधन मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने संबंधित विभागों को यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्किंग प्रबंधन बेहतर बनाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों शहरों के नगर निगमों को प्रमुख स्थानों पर यातायात संकेतक और सूचना पट्ट लगाने तथा मंडलायुक्तों को व्यवस्था में कमियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर करने को कहा। शुक्रवार को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कर हादसों की आशंका वाले स्थानों और जोखिमपूर्ण समय की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल बसों सहित भारी यात्री वाहनों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने बताया कि जम्मू में सड़क किनारे पार्किंग के लिए 17 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से तीन पार्किंग स्थल चालू हैं, जबकि सात स्थान विक्रेताओं को आवंटित किए गए हैं। श्रीनगर में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के 300 पार्किंग स्थानों की निगरानी स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। श्रीनगर नगर निगम व्यवस्थित पार्किंग क्षेत्रों की पहचान और नियमन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना तैयार कर रहा है। जम्मू नगर निगम ने भी पार्किंग प्रबंधन के लिए अलग प्रकोष्ठ गठित किया है। भविष्य में पार्किंग संबंधी निविदाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को शामिल करने की योजना है। मुख्य सचिव ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा।

गांदरबल में लंपी बीमारी पर अलर्ट पशुपालकों को सतर्कता की सलाह

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। गांदरबल जिले में लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए जन-जागरूकता परामर्श जारी किया है। विभाग ने पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने, संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने और प्रभावित क्षेत्रों से पशुओं की आवाजाही रोकने की अपील की है। पिछले महीने जिले के कई गांवों में 350 से अधिक पशुओं के इस बीमारी की चपेट में आने के बाद यह कदम उठाया गया है।



◆संक्रमित पशुओं को अलग रखने और टीकाकरण कराने की अपील, मदद के लिए हेल्पलाइन 1962 जारी

विभाग ने पशुपालकों से सतर्क रहने और पशु चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करने को कहा है।विभाग के अनुसार, लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक विषाणुजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, त्वचा पर सख्त गांठें, ग्रंथियों में सूजन, आंखों और नाक से स्राव आना, भूख कम लगना तथा दूध उत्पादन में गिरावट शामिल हैं। गंभीर मामलों में पशुओं को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और उनकी मौत भी हो सकती है। यह बीमारी मच्छरों, मक्खियों और अन्य काटने वाले कीड़ों के अलावा संक्रमित पशुओं तथा दूषित उपकरणों के संपर्क से फैल सकती है।

पशुपालन विभाग ने पशुओं का नियमित टीकाकरण कराने, पशुशाला की साफ-सफाई रखने, कीटाणुशोधन करने और काटने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। नए लाए गए पशुओं को कुछ समय तक अलग रखने और संदिग्ध पशुओं को बेचने या दूसरी जगह ले जाने से बचने को कहा गया है।

रामबन के खड़ी क्षेत्र में पुलिस का तलाशी अभियान

पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल पर रामबन पुलिस सतर्क, खड़ी में तलाशी अभियान जारी

भारतेंदु संवाददाता, ऊधमपुर



◆पाकिस्तान से संपर्कों की जांच तेज, रामबन में संदिग्धों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने शनिवार को खड़ी क्षेत्र में घेराबंदी एवं तलाशी अभियान (कासो) चलाया। इस दौरान पाकिस्तान में रह रहे जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों (जेकेएनओपी) और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) से जुड़े आवासों की तलाशी ली गई। पुलिस ने परिजनों को संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल और संचार के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी।

पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी सत्यापन करना और क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना था। तलाशी के दौरान संबंधित परिवारों के सदस्यों के मोबाइल फोन की भी जांच की गई। पुलिस ने लोगों को किसी भी असामान्य संपर्क या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को देने के लिए कहा।

पुलिस ने विशेष रूप से पाकिस्तान से आने वाली संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल और अन्य संचार माध्यमों के जरिए होने वाले संपर्कों को गंभीरता से लेने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समय पर सूचना मिलने से संभावित खतरे की जांच करने में मदद मिल सकती है।

अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाने और लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सत्यापन का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान करना है।

रामबन पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की। पुलिस के अनुसार, जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तथा जांच अभियान जारी रहेंगे। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में सहयोग करने का आग्रह किया।

हत्या मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



फाईल फोटो।

हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजाश्रीनगर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। श्रीनगर की एक अदालत ने वर्ष 2022 में बटमालू पुलिस थाने में दर्ज हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एफआईआर संख्या 109/2022 से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाफिजा बेगम, परवेज अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज अहमद डार को दोषी करार दिया। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 302, 120-बी और 201 के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

श्रीनगर पुलिस ने इस फैसले को मामले की जांच और प्रभावी अभियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम बताया।

जलसंचय 60 से 70 लाख लीटर पानी सहेजेंगे जलाशय, खेती को बढ़ावा और पलायन पर लगेगी रोक

लद्दाख के सोध में बनेंगे दो जलाशय, दूर होगा जल संकट

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल जिले के सोध ब्लाक में प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत दो जलाशयों की आधारशिला रखी। लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे इस क्षेत्र के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जलाशयों के निर्माण से स्थानीय लोगों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और जल संकट के कारण गांवों से हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। उपराज्यपाल ने बताया कि दोनों जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 60 से 70 लाख लीटर होगी। इनके निर्माण कार्य को नवंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीणों को खेती-किसानी के लिए जरूरी संसाधन मिल सकेंगे।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए बयान में कहा कि सोध के निवासियों की ओर से व्यक्त किया गया आभार उन्हें गहराई से प्रभावित कर गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे थे। दो सितंबर 2026 को लद्दाख की सांसद हनीफा जान के साथ सोध क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने जल संकट की गंभीर स्थिति को करीब से देखा था। पानी की कमी के कारण यहां कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। हालात ऐसे थे कि कुछ ग्रामीणों को आजीविका के लिए अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।

इस स्थिति को देखते हुए दौरे के बाद जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि आसपास के ग्लेशियरों और अन्य संभावित जल स्रोतों की पहचान की जाए। साथ ही इन स्रोतों से पानी को गांवों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार की जाए, ताकि लोगों को नियमित जल आपूर्ति मिल सके और कृषि गतिविधियों को बचाया जा सके।

प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत जलाशयों का निर्माण क्षेत्र में जल संरक्षण और जल उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। योजना के अनुसार आसपास की ग्लेशियर धाराओं से मिलने वाले पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पूरे साल पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलने के साथ खेती-किसानी को भी सहारा मिलेगा।

प्रशासन को उम्मीद है कि जलाशयों के निर्माण से पानी की किल्लत का दीर्घकालिक समाधान निकालने में सहायता मिलेगी। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर कृषि और आजीविका से जुड़े अवसर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे जल संकट के कारण होने वाले पलायन पर भी अंकुश लगने की संभावना है। उपराज्यपाल ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीनगर पुलिस ने चार अधिकारियों को दी विदाई

वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवाओं, समर्पण और पेशेवर योगदान की सराहना की

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

श्रीनगर पुलिस ने जिला पुलिस लाइंस में आयोजित समारोह में चार निवर्तमान अधिकारियों को विदाई दी। इनमें नेहा जैन (आईपीएस), शब्बीर खान (जेकेपीएस), शाह उमर (जेकेपीएस) और हिलाल खालिक भट (जेकेपीएस) शामिल रहे। इस दौरान अधिकारियों की समर्पित सेवाओं, पेशेवर दक्षता और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके योगदान की सराहना की गई।

समारोह की अध्यक्षता कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार सिंह (आईपीएस) ने की। मध्य कश्मीर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजीव पांडे (आईपीएस) और श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. जी.वी. संदीप चक्रवर्ती (आईपीएस) सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों ने निवर्तमान अधिकारियों की कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया। कानून-व्यवस्था मजबूत करने, शांति बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिस व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।

अधिकारियों ने कहा कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अनुशासन, सत्यनिष्ठा, आपसी विश्वास और टीम भावना बेहद जरूरी हैं। पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से ही चुनौतियों का सामना करते हुए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। निवर्तमान अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में इन मूल्यों को बनाए रखा और विभागीय जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

कार्यक्रम के दौरान सहकर्मियों ने साथ काम करने के अनुभवों और पेशेवर उपलब्धियों को भी याद किया। समारोह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सौहार्द तथा सहयोग के संबंधों को संजोने का अवसर दिया।

अंत में वरिष्ठ अधिकारियों ने चारों निवर्तमान अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी आगे भी इसी समर्पण, ईमानदारी और

रावण के पुतले नहीं, अपने भीतर का अहंकार जलाएं



एआई निर्मित चित्र।

भारतीय संस्कृति में दशहरा अथवा विजयादशमी असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान श्रीराम द्वारा रावण का वध केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के लिए शाश्वत संदेश है। यह पर्व हमें आत्ममंथन करने और अपने भीतर की बुराइयों को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले जलाने के बाद भी समाज में अहंकार, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या और असहिष्णुता क्यों बनी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पर्व के बाहरी स्वरूप को अपना लिया है, लेकिन उसके वास्तविक संदेश को जीवन में उतारना भूल गए हैं?

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन आदर्श आचरण की मिसाल है। उन्होंने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर कर्तव्य, मर्यादा और लोककल्याण को प्राथमिकता दी। पिता के वचन की रक्षा के लिए राजमहल का वैभव त्यागकर वनवास स्वीकार करना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना उनके चरित्र की महानता दर्शाता है। उनका जीवन सिखाता है कि महानता अधिकारों के उपभोग में नहीं, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन में निहित है। वास्तविक समर्पण शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से सिद्ध होता है। दशहरा हमें इसी रामत्व को अपनाने और अपने भीतर के अहंकार तथा स्वार्थ पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।

रावण का चरित्र ज्ञान के साथ विवेक और विनम्रता के महत्व को समझाता है। वह विद्वान, शक्तिशाली और शिवभक्त था, लेकिन अहंकार और अनियंत्रित इच्छाओं के कारण उसका पतन हुआ। उसके पास ज्ञान और सामर्थ्य की कमी नहीं थी, फिर भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने और समय रहते स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है, जब वह विवेक, विनम्रता और सदाचार के रूप में हमारे व्यवहार में दिखाई दे। केवल पुस्तकीय ज्ञान, धार्मिक प्रवचन या नैतिकता की बातें किसी व्यक्ति को महान नहीं बनातीं। यदि शिक्षित व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसकी शिक्षा अधूरी है।

आज के समय में दशहरे का संदेश शिक्षा, परिवार और सामाजिक जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने और जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चों में ईमानदारी, संवेदनशीलता, सहनशीलता और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित करना भी जरूरी है। माता-पिता और शिक्षकों को अपने आचरण से इन मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उपदेशों से अधिक व्यवहार से सीखते हैं।

आधुनिक युग में विज्ञान, तकनीक और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, लेकिन जानकारी की प्रचुरता अपने आप में विवेक की गारंटी नहीं है। जब पद अहंकार का कारण बनता है, धन शोषण का साधन बनता है और शक्ति कमजोर लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है, तब रावण की प्रवृत्तियां समाज में दिखाई देने लगती हैं। इसके विपरीत, कठिन परिस्थितियों में सत्य का साथ देना, दूसरों के सम्मान की रक्षा करना और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करना राम के आदर्शों को जीवित रखता है।

दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने में है। क्रोध के समय संयम रखना, सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना और असफलता से सीखना भी जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमारा ज्ञान हमारे व्यवहार में दिखाई देता है और क्या हमारी सफलता ने हमें बेहतर इंसान बनाया है? इसलिए दशहरे की सार्थकता केवल उत्सव, आतिशबाजी और रावण के पुतले के दहन तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

विक्रम वर्मा, स्वतंत्र लेखक
वम्बा, हिमाचल प्रदेश

देवी स्वरूप का गुणार्थ – हृदय की भाषा में सौंदर्य

आदि शंकराचार्य और अनेक आचार्यों ने देवी के स्वरूप का बड़ा ही बारीकी से वर्णन किया है। वे कैसी दिखती हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके हाथों में कौन-सी मुद्राएँ हैं, इन सभी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म शक्ति होते हुए भी देवी का इतना विस्तृत चित्रण क्यों किया गया और इसका असली गुणार्थ क्या है? वास्तव में सौंदर्य का जो रस है, वह बुद्धि की भाषा में नहीं, बल्कि हृदय की भाषा में ही अनुभव किया जा सकता है। सौंदर्य का विश्लेषण नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी की आँखों की प्रशंसा में हम कहते हैं, 'कमलनयन।' अब कोई पूछे कि कमल की कौन-सी पंखुड़ियों जैसी आँखें हैं, तो यह हास्यास्पद लगेगा। आँखों की सुंदरता का अनुभव केवल हृदय से किया जा सकता है। उसमें बारीक तर्क लगाने से रस चला जाता है। सौंदर्य को सौंदर्य के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें बुद्धिगत विश्लेषण करने जाएंगे, तो असफल हो जाएंगे, क्योंकि वह हृदय में महसूस करने की चीज है, बुद्धि से उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता।

इसी प्रकार देवी के सौंदर्य और अलंकरण का विस्तार भक्ति का एक काव्यात्मक रूप है। देवी सूक्ष्म शक्ति हैं और उन्हें शब्दों में बाँधना संभव नहीं है। फिर भी शास्त्रकारों ने उनके आभूषणों, वस्त्रों और मुद्राओं का वर्णन किया, ताकि साधक के भीतर सौंदर्य और भक्ति का रस जागृत हो। शास्त्रों में देवी के हाथों की मुद्राओं का भी विशेष महत्व है। एक हाथ से वे वरद मुद्रा में कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जबकि दूसरे हाथ की अभय मुद्रा भय को दूर करने का संदेश देती है। वस्त्र और आभूषण केवल बाहरी सजावट नहीं हैं, बल्कि वे देवी के गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं। माँ लक्ष्मी का कमल के फूल पर विराजमान होना



एआई निर्मित चित्र।

धन की चंचलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि माँ सरस्वती का पत्थर पर विराजमान होना ज्ञान की स्थिरता को दर्शाता है।

यहाँ एक और गहरी बात है कि प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति में दोहराव का विशेष स्थान होता है। कोई गीतकार एक ही पंक्ति कई बार गाता है, प्रेमी



गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

अपनी प्रेमिका को बार-बार एक ही बात लिखता है, 'मैं तुमसे प्यार करता हूँ।' बुद्धि कहती है कि एक बार कह दिया, तो काफी है, लेकिन दिल बार-बार कहने और सुनने की इच्छा रखता है। यही प्रेम का स्वभाव है। देवी की स्तुतियाँ, उनके रूप-वर्णन और उनके नामों की पुनरावृत्ति भी इसी प्रेम-रस की झलक है। इनके माध्यम से भक्त अपने आराध्य के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को बार-बार व्यक्त करता है।

इस दृष्टि से देवी का अलंकरण और स्वरूप-वर्णन केवल बौद्धिक व्याख्या नहीं, बल्कि साधक के भीतर रस और भक्ति जगाने का साधन है। जब हम देवी की सुनहरी आभा, रत्नजटित आभूषणों और दिव्य वस्त्रों की कल्पना करते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिव्यता में डूबने लगता है। यह ध्यान की एक पद्धति है, जिसमें बाहरी चित्रण के माध्यम से भीतर की चेतना सजग होती है। देवी के रूप का ध्यान करते हुए साधक अपने मन में सौंदर्य, करुणा, शक्ति और माधुर्य जैसे गुणों को अनुभव करने का प्रयास करता है।

यदि हम इन विवरणों का केवल बौद्धिक विश्लेषण करेंगे, तो उनके वास्तविक भाव को समझने से चूक सकते हैं। यह उसी तरह है, जैसे किसी फूल की सुगंध का विश्लेषण करने की कोशिश करना। सुगंध का आनंद उसे अनुभव करने में है, न कि केवल प्रयोगशाला की रिपोर्ट में। देवी का स्वरूप भी हृदय की अनुभूति है, बुद्धि का गणित नहीं। अत: देवी के स्वरूप-वर्णन का गुणार्थ यही है कि हम सौंदर्य और भक्ति को केवल बौद्धिक कसौटी पर न तौलें, बल्कि उन्हें हृदय से ग्रहण करें। देवी का अलंकरण, उनकी मुद्राएँ और उनका सौंदर्य हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में भी करुणा, शक्ति, माधुर्य और प्रेम के गुण होने चाहिए। यही देवी की उपासना का सार है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपत्ति के लिए अपनापन भूली संतान, बेसहारा हुए बुजुर्ग

एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में वृद्धों की संख्या आए-दिन तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही उनकी संतानों द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के अप्रत्याशित गंभीर घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि अक्सर मीडिया में देखने-सुनने को मिलती रहती है।

वृद्धावस्था का महत्व और बुजुर्गों का सम्मान



एआई निर्मित चित्र।

इस समस्या की जटिलता को देखते हुए संतानों द्वारा अपने बुजुर्गों की उपेक्षा रोकने और उनकी 'जीवन संध्या' को सुखमय बनाने के लिए देश में सबसे पहले हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने अपने 2002 के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान 'वृद्ध माता-पिता एवं आश्रित भरण-पोषण कानून' बनाया था।

इस कानून के अंतर्गत संतानों द्वारा पीड़ित माता-पिता को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत करने का अधिकार दिया गया व दोषी पाए जाने पर संतान को माता-पिता की संपत्ति से वंचित करने, सरकारी अथवा सार्वजानिक क्षेत्र में नौकरियां न देने तथा सेवारत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से समुचित राशि काटकर माता-पिता को देने का प्रावधान किया गया।

धूमल द्वारा लिए गए इस निर्णय की हिमाचल प्रदेश में ही नहीं यद्यपि देश के हर कोने में सर्वत्र प्रशंसा हुई। तदोपरांत बुजुर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की संसद ने भी 'अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण विधेयक -2007' द्वारा बुजुर्गों की देखभाल न करने पर तीन माह तक कैद का प्रावधान किया और इसके विरुद्ध अपील की अनुमति भी नहीं है। इसके पश्चात असम और दिल्ली जैसे राज्य सरकारों ने भी इसका अनुसरण किया और अब तेलंगाना सरकार भी जल्द ही ऐसे कानून को अमलीजामा पहनाने जा रही है, जो स्वागतयोग्य ही नहीं, बल्कि प्रशंसनीय भी है। आज सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे कानून बनाने की आखिर आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वास्तव में आज संतानें अपने मां-बाप की देखभाल के कर्तव्य से विमुख होती जा रही और हमारे स्वाभिमानी और बुजुर्ग आए-दिन भावनात्मक यातनाओं से गुजर रहे हैं, यह अत्याधिक पीड़ादायक विषय है। देश के हर कोने से संतानों द्वारा बुजुर्गों को प्रताड़ित करने के गंभीर मामले रोजमर्रा प्रकाश में आते रहते हैं।

मां-बाप बच्चों का लालन-पालन बड़ी ही मुश्किल व अपनी जिंदगी की समस्त पूंजी इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि शायद वृद्धावस्था की आने वाली जीवन संध्या में औलाद उनकी लाठी का सहारा बनेगी। यही नहीं,वे उनकी परवरिश के लिए इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपने सुख-दु:ख की चिंता भी कदापि नहीं रहती है। पहले बच्चों की परवरिश, शिक्षा, भविष्य को संवारने और उनका करियर बनाने के लिए येन-केन-प्रकारेण वह दिन-रात प्रयासरत रहते हैं। इसके उपरांत भी संतानें आज उन्हें दरकिनार रही हैं और ऐसे में बुजुर्गों को संतान के सहारे की दरकार हो रही है। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि जिन वृद्धों की कमाई का कोई साधन नहीं है वह दो वक्त की रोटी तक के लिए जहां मोहताज हैं, वहीं दर-दर की ठोकरें खाने को भी विवश हैं।

लगता है कि आज की पीढ़ी अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों को तिलांजलि देकर पतन की ओर जा रही है अथवा विमुख हो रही है। यह सत्य है कि मां-बाप जैसे पवित्र रिश्ते को अधिकांश वर्तमान पीढ़ी अपनी स्वार्थ सिद्धी एवं व्यवहार के चलते उन्हें अपमानित करने में उतारु है। कई प्रकरण ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि मां-बाप ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी, जिसके कुछ समय उपरांत बहू-बेटे द्वारा उनकी पिटाई करने, धमकाने और कई मर्तबा खाना भी न देने पर न्याय के लिए उन्हें न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए कुछ समय पूर्व 'बाम्बे हाई कोर्ट' के न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने कहा कि आज के युग में माता-पिता द्वारा अपने बच्चों की परवरिश में कुछ गड़बड़ी है तथा एक बेटा अपने वृद्ध माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बजाए अदालत में घसीट रहा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

एक शाम, एक हंसी और प्रेम के अनगिनत रंग



एआई निर्मित चित्र।

साल 2004, हरिद्वार। गंगा का तट, शाम का समय और आती हुई गरमियों की नन्हीं कोंपलें। मैं हर की पैड़ी पर अकेला बैठा गंगा की अनगिनत लहरों को निहार रहा था। मेरे सामने गंगा अपने विशाल हृदय में अनंत जल समेटे संसार के पापों को धोती हुई निश्चल बह रही थी। थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली थी। मेरे लिए संसार श्याम-श्वेत था। रंग दिखाई तो देते थे, पर उनका एहसास कभी मेरे मन तक नहीं पहुंचा था। धरती, आकाश, फूल, पत्ते, तितलियां, नदियां और पहाड़, सब कुछ मुझे उन्हीं दो रंगों में दिखाई देता था।

उसी शाम अचानक मेरे कानों में एक उन्मुक्त हंसी सुनाई दी। उसके साथ एक धीमी आवाज आई, 'अच्छा, फिर? फिर क्या हुआ?' मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर सीढ़ियों पर बैठा एक युवक और युवती दिखाई दिए। युवती ने अपना सिर युवक के कंधे पर रखा हुआ था। युवक उसके कानों में कुछ कहता और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी में गंगा की लहरें, बहते दीपक और घाट का वातावरण जैसे समा गए थे।

मैं उन्हें एकटक देखता रहा। उनके बीच कुछ ऐसा था, जिसे शब्दों में समझ पाना मेरे लिए कठिन था। उनकी हंसी, मस्ती और नटखटपन के आसपास एक अद्भुत आभामंडल बन रहा था। पहली बार मुझे लगा कि मेरी आंखें किसी अनजानी दुनिया को देख रही हैं। जब युवती खिलखिलाती, तो आसपास गुलाबी रंग बिखर जाता। जब वह शरारत से युवक की ओर देखती, तो वातावरण हल्के केसरिया रंग में रंग जाता। और जब दोनों एक-दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखते, तो लगता जैसे चांद के पास कोई सितारा चमक रहा हो।

उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रंग केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं हैं। शायद रंग एहसास होते हैं, जो हमारे मन के परिदृश्य पर बिखरकर आत्मा को विभोर कर देते हैं। अलग-अलग एहसास आपस में घुलमिलकर नए रंग बनाते हैं और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। रंगों की इस दुनिया की गहराई इतनी अनंत है कि हम शायद जीवन भर इसकी थाह नहीं पा सकते।

इन सभी रंगों में प्रेम का रंग सबसे अनोखा है। वह सबसे चमकीला, सबसे मधुर और सबसे गहरा एहसास है। उसकी पहचान वही कर सकता है, जो स्वयं उसमें डूब चुका हो। उस युवक और युवती को प्रेम में डूबा देखकर मेरी श्याम-श्वेत दुनिया बदल गई। उनकी हंसी और उनके बीच का अपनापन मेरी आत्मा में रंगों की नई दुनिया बसा गया।

कुछ देर बाद गंगा आरती शुरू हुई। घाट लोगों से भर गया और वे दोनों कहीं चले गए। मैं उसी रात घर लौट आया, लेकिन अब मेरी तलाश बदल चुकी थी। मैं उन अनजाने रंगों को महसूस करने लगा था, जिनसे यह दुनिया भरी हुई है। आज भी, इतने वर्षों बाद जब जीवन में श्याम-श्वेत रंग हावी होने लगते हैं, तो मैं अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर हर की पैड़ी की उस शाम को याद करता हूं। चांद के पास चमकते सितारे के नीचे बैठे उन दोनों की उन्मुक्त हंसी आज भी मेरे भीतर गूंज उठती है। और मेरी आत्मा एक बार फिर प्रेम के उन अद्भुत रंगों से सराबोर हो जाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सुमित शर्मा
शाहपुर



कविता

साहस की उड़ान!

अशोक सिंह गुलेरिया
हमीरपुर

आसमान में संकट था,
उम्मीद डगमगाई थी,
हर चेहरे पर डर की एक परछाईं छाई थी।
खुद घायल होकर भी जिसने हौसला नहीं खोया,
दूसरों की सांसों के लिए अपना दर्द भुलाया।
एक साहस उठा,
फिर कई हाथ साथ आए,
अनजान थे जो कल तक, आज अपने बन जाए।
किसी ने दर्द बांटा, किसी ने सहारा दिया,
किसी ने टूटते हौसलों को फिर से हौसला दिया।
यही तो मानवता है,
यही सच्चा धर्म है,
मुसीबत में किसी के काम आना सबसे बड़ा कर्म है।
जब राह कठिन हो,
किसी का हाथ थाम लेना,
गिरते हुए इंसान को फिर से संभाल लेना।
न जाति की दीवार हो, न देश का भेद रहे,
न भाषा की दूरी हो,
न मन में कोई खेद रहे।
इंसान के लिए इंसान हर बार खड़ा रहे,
हर मुश्किल में प्रेम और विश्वास का दीप जला रहे।
क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान यही है,
दूसरों के दुख में साथ निभाना ही सही है।
जब मिलकर हाथ बढ़ाते हैं, मुश्किलें हार जाती हैं,
मानवता की राह पर खुशियां लौट आती हैं।

संपादकीय

विकास का फायदा किसे?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान उत्साह बढ़ाने वाला है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। अक्टूबर 2026 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के मुताबिक, जुलाई में विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह, वित्त वर्ष 2027-28 के लिए भी विकास दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। यह आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसकी विकास क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भरोसे को दर्शाता है। हालांकि, आर्थिक विकास के इन सकारात्मक संकेतों के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि तेज विकास का लाभ देश की आम जनता तक किस हद तक पहुंच रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का वास्तविक आकलन केवल विकास दर के आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आने वाले बदलावों से भी किया जाना चाहिए।

भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में निवेश, सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार और सरकारी पूंजीगत व्यय जैसे कारक आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कई अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती और अनिश्चितता का सामना कर रही हैं। ऐसे में भारत की विकास दर का बेहतर अनुमान देश के लिए सकारात्मक संकेत है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और नए उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक सफलता केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से नहीं मापी जा सकती। इसका आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि आर्थिक विकास से रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए, लोगों की आय में कितनी वृद्धि हुई और उनकी क्रय शक्ति कितनी मजबूत हुई। यदि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंचता, तो आर्थिक प्रगति का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

दरअसल, आम जनता के लिए अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबसे प्रत्यक्ष अर्थ महंगाई से राहत है। यदि देश की विकास दर बढ़ रही है, लेकिन खाद्य पदार्थों, दवाइयों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता है, तो आम परिवारों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस करना कठिन हो जाता है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर महंगाई का असर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से घरेलू बजट प्रभावित होता है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत परिवारों की बचत को सीमित कर देती है। ऐसे में आर्थिक विकास के साथ महंगाई पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए कीमतों की नियमित निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की रफ्तार के साथ रोजगार के अवसर बढ़ें, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और छोटे कारोबारियों की लागत नियंत्रित रहे। कृषि उत्पादन, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में सुधार से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और परिवहन लागत का भी महंगाई पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। रोजगार सृजन के लिए लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना तथा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों से मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त गति मिलेगी।

बहरहाल, आईएमएफ का बढ़ा हुआ विकास अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से उत्साहजनक है, लेकिन यह सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारियों का विस्तार करने का अवसर भी है। मजबूत अर्थव्यवस्था तभी सार्थक मानी जाएगी, जब आम आदमी की आय बढ़े, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और उसकी रसोई का बजट महंगाई से न बिगड़े। इसके लिए विकास नीतियों का केंद्र आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। सरकार को निवेश और उत्पादन बढ़ाने के साथ सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। आर्थिक विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचने से ही लोगों की बचत बढ़ेगी और उनकी भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब चुनौती विकास दर को बनाए रखने के साथ उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने की है। यही आर्थिक प्रगति की असली कसौटी होगी।

-शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

फर्श से अर्श तक का सफर

ओम पुरी भारतीय सिनेमा के उन दिग्गज अभिनेताओं में शामिल थे, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे ओम पुरी का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता टेक चंद पुरी रेलवे और भारतीय सेना में कार्यरत थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ओम पुरी को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने चाय की दुकान पर काम किया और रेलवे पटरियों के आसपास से कोयला इकट्ठा करके परिवार की मदद की। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना पूरा किया।



ओम पुरी
जन्म : 18 अक्टूबर 1950

ओम पुरी ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रंगमंच की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में भी अध्ययन किया। अभिनय के प्रति उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती, उर्दू और मराठी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वह अंग्रेजी और कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में भी नजर आए।

ओम पुरी ने अपने करियर में गंभीर, सामाजिक और यथार्थवादी भूमिकाओं से लेकर हास्य किरदारों तक को बखूबी निभाया। आक्रोश, आरोहण और अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। वहीं सद्गति और तमस जैसे टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का प्रभावशाली परिचय दिया। दूसरी ओर जाने भी दो यारो, चाची 420, हेरा फेरी, चुप चुप के और ढोल जैसी फिल्मों में उनके हल्के-फुल्के और हास्यपूर्ण किरदारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। निर्देशक श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी के साथ उनका विशेष जुड़ाव रहा। अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में भी ओम पुरी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। माय सन द फैनैटिक और ईस्ट इज ईस्ट जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ईस्ट इज ईस्ट में उनके काम के लिए उन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन भी मिला।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

विधायक संजय अवस्थी ने किया स्वागत काउंटर का शुभारंभ

अर्की अस्पताल में मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। नागरिक अस्पताल अर्की में मरीजों को जल्द ही डायलिसिस और अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शनिवार को अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने अस्पताल में स्वागत एवं पंजीकरण काउंटर और आधिकारिक वेबसाइट

◆ पार्किंग और आवास निर्माण के लिए बजट दिलाने का आश्वासन

का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। स्वागत एवं पंजीकरण काउंटर के माध्यम से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उपचार संबंधी आवश्यक जानकारी और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।

वहीं, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अस्पताल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को सुविधाएं प्राप्त करने में भी आसानी होगी। विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने और आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक अस्पताल अर्की से विधानसभा क्षेत्र के साथ आसपास के इलाकों के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं।



उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अस्पताल में आवास और पार्किंग निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित प्राक्कलन के आधार पर आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मरीजों को समयबद्ध एवं बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधायक ने 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के अभिभावकों से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण करवाने की अपील की।

एचपीवी संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा

खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले संक्रमण और इससे संबंधित गंभीर बीमारियों, विशेषकर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा कम करने में यह टीका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में खंड कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सी.डी. बंसल, नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा शर्मा, एसडीएम निशांत तोमर, डीएसपी नवीन झालटा, बीडीओ तन्मय कंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

कांगड़ा में बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल (पुरुष) चैंपियनशिप-2026 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के 15 कॉलेजों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पाटियाल ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अनूप कुमार रतन ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच विकसित होती है। साथ ही, युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी खेल अहम भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। मेजबान एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैजनाथ की टीम को 65-05 के बड़े अंतर से पराजित किया। भोरंज ने हमीरपुर को 43-42 से हराया, जबकि बिलासपुर ने सोलन को 37-30 से शिकस्त दी। पालमपुर ने कोटशेरा को 37-31 से पराजित किया। वहीं, संजौली की टीम ने नाहन को कड़े मुकाबले में 49-46 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

मंडी में 50 से अधिक युवाओं का चयन, विदेश में मिलेगी नौकरी

'सुक्खू सरकार' की पहल से विदेशों में खुल रहे रोजगार के द्वार

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल से युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी स्थित जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल करियर सेंटर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की कंपनी में भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य

◆ युवाओं के सपनों को उड़ान, यूएई में नौकरी के अवसर

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड तथा श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भर्ती अभियान में प्रदेश के आठ जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति से करीब 200 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया। भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में 50 से अधिक युवाओं का सहायक, तकनीकी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर सहित विभिन्न पदों के लिए चयन हुआ है।

चयनित अभ्यर्थियों को पद और निर्धारित शर्तों के अनुसार लगभग 37,700 से 45,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त रहने-खाने, वीजा, चिकित्सा सुविधा, साप्ताहिक अवकाश और अतिरिक्त कार्य के लिए अलग भुगतान जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। चयनित युवाओं को 30 दिन का सवेतन वार्षिक अवकाश तथा प्रतिवर्ष घर आने-जाने के हवाई टिकट के लिए लगभग 71,000 रुपये देने का प्रावधान है।



निजी एजेंटों पर निर्भरता कम करने की दिशा में हिमाचल सरकार की पहल, सभी चयनित अभ्यार्थी।

युवाओं ने जताया आभार

भर्ती साक्षात्कार में शामिल युवाओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर भर्ती होने से निजी एजेंटों के माध्यम से विदेश में नौकरी पाने के दौरान होने वाली धोखाधड़ी की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा से रोशन हुआ जिला स्तरीय विज्ञान मंच



भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल में आयोजित 33वीं जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शनिवार को समापन हुआ। दो दिवसीय आयोजन में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने क्विज, एक्टिविटी कॉर्नर, साइंस मॉडल, गणितीय ओलंपियाड, साइंस स्किट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। क्विज के विभिन्न वर्गों में मिनर्वा स्कूल घुमारवीं, डीएवी बरमाणा और ग्लोरी स्कूल बिलासपुर के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। साइंस मॉडल में कुठेड़ा और मिनर्वा स्कूल के विद्यार्थी अव्वल रहे, जबकि गणितीय ओलंपियाड में भी मिनर्वा और शिवा इंटरनेशनल के विद्यार्थियों ने बाजी मारी। साइंस स्किट में डीएवी घुमारवीं प्रथम रहा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

आईटीआई मंडी के विद्यार्थियों ने समझीं बचत ऋण और बीमा योजनाओं की बारीकियां



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सौलीखड्ड शाखा ने नाबार्ड के सौजन्य से आईटीआई मंडी में एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। शाखा प्रबंधक अनिल धरवाल ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बैंक की बचत एवं ऋण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण ऋण योजना, सपनों का संचय योजना और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के लाभ बताए। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी जागरूक किया। शिविर में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सावधानियों और साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। हिम पैसा ऐप की सुविधाएं भी समझाई गईं। शिविर में लगभग 60 से 65 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

बल्ह की पंचायतों में घर-घर से उठेगा कूड़ा

भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर, राजेन्द्र चौहान। बल्ह विकासखंड की पंचायतों को स्वच्छ बनाने के लिए अब घर-घर से कूड़ा-कचरा उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस अभियान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कोठी में पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी राजेन्द्र चौहान ने पंचायत विकास योजना, 16वें वित्त आयोग, निधि के स्रोत और पंचायतों की शक्तियों की जानकारी दी। पूर्व जिला पंचायत अधिकारी राजेन्द्र धीमान ने न्यायिक शक्तियों, जबकि अन्य अधिकारियों ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायती राज अधिनियम, ग्रामसभा और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। शिविर में कोठी, सिध्यानी, वैरी, बाल्ट और डहणू पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रिवालसर स्कूल में सजा हिमाचल-केरल के व्यंजनों का संगम



भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत व्यंजन संगम का आयोजन किया गया। विद्यालय के पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग द्वारा आयोजित इस फूड फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश और केरल के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। प्रधानाचार्य विक्रम राठौर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयोजिका शशि निहाल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने हिमाचल के सिड्डू, मदरा और बबरू तथा केरल के इडली-सांभर, डोसा और पायसम तैयार किए। विद्यार्थियों ने पाक कला और आतिथ्य सत्कार का हुनर दिखाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

विद्यार्थियों को दूषित पानी से मिलेगी मुक्ति ई-लाइब्रेरी में लगेंगे पर्दे

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी में जल्द ही विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल और पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। शनिवार को सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने पुस्तकालय के नए और पुराने भवन का निरीक्षण कर विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विद्यार्थियों ने वाटर कूलर से मटमैला पानी आने और ई-लाइब्रेरी की खिड़कियों पर पर्दे न होने से कंप्यूटर स्क्रीन पर तेज धूप पड़ने की शिकायत की। विधायक ने एक सप्ताह के भीतर यूवी वाटर प्योरीफायर और पर्दे लगवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुस्तकालय के बाहरी पार्क में उगी झाड़ियों और घास की सफाई करवाने के लिए नगर परिषद को आवश्यक निर्देश भी दिए।

दो दिन में सर्वे कर तैयार करें विकास कार्यों के एस्टीमेट : सुनील शर्मा बिट्टू

भारतेन्दु संवाददाता, अनिल कुमार, हमीरपुर। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर बाईपास के साथ लगते बारल, लोहारडा और आसपास के क्षेत्रों में सीवरेज, पक्की सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए शीघ्र बजट का प्रावधान किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम क्षेत्र की जनसमस्याएं सुनते हुए उन्होंने कहा कि यहां फुटपाथ, हाई मास्ट लाइट्स और रेन शेल्टर का निर्माण भी करवाया जाएगा। बारल के कुछ परिवारों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई पाइपलाइन का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।

सुनील शर्मा बिट्टू ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां नई सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता है, वहां अधिकारी दो दिनों के भीतर सर्वे पूरा करें, ताकि एस्टीमेट तैयार कर बजट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर जिले में विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जा रही है। सरकार क्षेत्र के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नींबू प्रजाति के पौधे भी वितरित किए।



बारल-लोहारडा में सीवरेज, सड़क और स्ट्रीट लाइट्स के लिए मिलेगा बजट।

एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 21.9 लाख की ठगी, दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। नगर निगम के चीफ सेनेटेशन ऑफिसर के बेटे को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का झांसा देकर 21.9 लाख रुपये ठगने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभिषेक और नीरज को लखनऊ और पटना से काबू किया। इससे पहले इस मामले में दो अन्य आरोपियों बंटी कुमार तिवारी और मोहम्मद जुबेर को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इस तरह मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।



पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने गुरुग्राम में 'द एडमिशन सॉल्यूशन' नाम से फर्जी काउंसलिंग सेंटर खोल रखा था। वे मेडिकल कॉलेज में कम फीस पर दाखिला दिलाने का झांसा देकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को निशाना बनाते थे। पठानकोट निवासी विक्रमजीत ने शिकायत में बताया कि उनके बेटे गौरव ने वर्ष 2025 में नीट की परीक्षा दी थी। इसके बाद आरोपियों ने फैजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का भरोसा देकर सितंबर से नवंबर 2025 के बीच नकद, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 21.9 लाख रुपये ठग लिए।

छापेमारी में खुला फर्जी सेंटर का राज

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने गुरुग्राम का कार्यालय बंद करने के बाद रायपुर में 'ब्राइटमार्ग' नाम से नया फर्जी सेंटर खोल लिया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्जी पहचान पत्र, डेबिट कार्ड और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित डेटा बरामद किया। एसपी विश्वजीत सिंह के अनुसार, गिरोह ने अन्य लोगों से भी करोड़ों रुपये की ठगी की आशंका है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गुरुग्राम से रायपुर तक फैला था फर्जी काउंसलिंग सेंटर का जाल, एमबीबीएस दाखिले के नाम पर 21.9 लाख ठगने वाले चार आरोपी गिरफ्तार।

स्कूल से घर जा रहे छात्र को ऑल्टो कार ने मारी टक्कर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्दरौर में स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र घायल हो गया, जबकि आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में जतिन पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव सनहोग (नेरी), जिला शिमला, जो वर्तमान में कन्दरौर में किराये के मकान में रह रहा है, ने बताया कि 16 अक्टूबर को स्कूल में छुट्टी होने के बाद वह घर लौट रहा था। इसी दौरान कन्दरौर की ओर से आ रही ऑल्टो के-10 कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसे चोटें आईं। टक्कर मारने के बाद चालक रुकने के बजाय मौके से भाग निकला। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सदर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।

केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में श्री साईं कॉलेज को मिली जगह

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के बधानी स्थित श्री साईं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'चिप्स टू स्टार्टअप' कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि संस्थान के साथ-साथ पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, माइक्रोप्रोसेसर और संबंधित तकनीकों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इसके तहत विद्यार्थियों को आधुनिक डिजाइन टूल्स, उन्नत तकनीकी संसाधनों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वास्तविक चिप डिजाइन परियोजनाओं पर काम करने के साथ स्वदेशी तकनीक और बौद्धिक संपदा के विकास में भी योगदान दे सकेंगे।

सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ेगा शिक्षण संस्थान

परियोजना का नेतृत्व प्रधान अन्वेषक प्रो. (डॉ.) विपिन गुप्ता कर रहे हैं, जबकि डॉ. मुकेश शुक्ला सह-प्रधान अन्वेषक हैं। कार्यक्रम से उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों को सेमीकंडक्टर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। इस उपलब्धि पर श्री साई ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज, एमडी तृप्ता पुंज, सीएमडी कंवर तुषार पुंज, उपाध्यक्ष रिया पुंज और कार्यकारी निदेशक सरदार रणजीत सिंह ने ईसीई विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे।



इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इससे विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

बिलासपुर कॉलेज में विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर, अमर सिंह ठाकुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से महाविद्यालय परिसर के सिट-आउट क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. अश्वनी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और परिसर में साफ-सफाई की। विद्यार्थियों ने आसपास बिखरे कचरे को एकत्रित कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करना रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने विभाग की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल किसी विशेष अभियान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से महाविद्यालय परिसर सहित अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी लिया।



शिक्षकों ने मनाया एकता और सौहार्द का उत्सव

प्रताप वर्ल्ड स्कूल में गरबा-डांडिया की धूम, शिक्षकों ने बांधा समां



भारतेन्दु संवाददाता, अशोक ठाकुर इंदौरा (कांगड़ा)। प्रताप वर्ल्ड स्कूल, इंदौरा में नवरात्रि की सप्तमी के अवसर पर शिक्षकों के लिए गरबा एवं डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया गया। रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा, मधुर संगीत और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। शिक्षकों ने गरबा और डांडिया की धुनों पर उत्साहपूर्वक भाग लेकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की।

विद्यालय की प्रबंध निदेशक डॉ. रीचा महाजन और प्रधानाचार्या रेनू परमार ने भी उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के बीच आपसी मेल-जोल, सहयोग और टीम भावना को मजबूत करना था। अंत में सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।

मंडी के पांच सौ साल के इतिहास को मिलेगा शोधपरक दस्तावेजी स्वरूप

मंडी की स्थापत्य विरासत और लोकगीत परंपरा पर विद्वानों ने की चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी के इतिहास विभाग और भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटैक) मंडी चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में मंडी नगर के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय 'मंडी नगर के 500 वर्ष का इतिहास: स्थापत्य विरासत एवं लोकगीत परंपरा का अध्ययन' रहा। कार्यक्रम में मंडी नगर की ऐतिहासिक विकास यात्रा, स्थापत्य कला, लोकगीतों में संरक्षित ऐतिहासिक स्मृतियों और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु आचार्य (डॉ.) ललित कुमार अवस्थी ने की, जबकि उपायुक्त अपूर्व देवगन मुख्य अतिथि और अधिष्ठाता छात्र कल्याण आचार्य राजेश कुमार शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इतिहास विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।

इंटैक मंडी चैप्टर के संयोजक नरेश मल्होत्रा ने संगोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए नगर की ऐतिहासिक विरासत के व्यवस्थित अध्ययन और संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

मंडी की गौरवगाथा

अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलगुरु आचार्य ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि मंडी की पांच शताब्दियों की ऐतिहासिक यात्रा हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने मंडी नगर के 500 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित विशेष 'मंडी500' लोगो तैयार किया है।



इस पुस्तक में नगर के इतिहास, स्थापत्य विरासत, राजनीतिक परंपराओं, सांस्कृतिक विकास को शोधपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य अतिथि उपायुक्त अपूर्व देवगन ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों को आवश्यक बताया।

मुख्य वक्ता एवं सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ललित कपूर ने मंडी की ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों और स्थापत्य विशेषताओं के माध्यम से नगर के विकास को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला। रंगकर्मी सीमा शर्मा ने लोकगीतों और पारंपरिक नाट्य विधाओं को समाज की सामूहिक स्मृति तथा सांस्कृतिक अनुभवों का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल

दो हजार खेल नर्सरियों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगी सरकार

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2,466 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 885 रोजगार मेलों और प्लेसमेंट अभियानों के माध्यम से 11,162 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला

◆ सक्षम युवा योजना के तहत 2.75 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता

है। सक्षम युवा योजना के तहत 2 लाख 75 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते और मानदेय के रूप में 657 करोड़ 27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। जुलाई 2025 में आयोजित सीईटी-ग्रुप सी परीक्षा में 13 लाख 48 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। ग्रुप-डी के लिए भी दोबारा सीईटी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 15 लाख 9 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।

उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल सहित विभिन्न चिन्हित पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट दी गई है।

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, 42 को सरकारी नौकरी

खेल सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2,000 खेल नर्सरियां और ग्रामीण क्षेत्रों में 421 इंडोर जिम स्थापित किए गए हैं। खेल ढांचे के विकास पर 321 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में 1,319 पदक विजेता खिलाड़ियों को 147 करोड़ 16 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए और 42 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलीं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को अवसर देकर, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर प्रदेश के विकास को गति देना है।

हरियाणा में 250 सीएम-ईईई स्कूल खुले

मेडिकल शिक्षा का विस्तार, हरियाणा में 12 वर्षों में खुले 12 नए मेडिकल कॉलेज

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम-श्री विद्यालयों की तर्ज पर 250 सीएम-ईईई स्कूल खोले गए हैं। पीएम-श्री और समग्र शिक्षा योजना के तहत 900 सरकारी



विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश की 441 अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से लगभग एक लाख विद्यार्थियों को नवाचार और अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नए राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा मौजूदा संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने के लिए 135 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में 84 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 33 महिला महाविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 17 जिलों में 44 करोड़ रुपये की लागत से 350 अटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए विशेष बसों की संख्या बढ़ाकर 893 की गई है। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतू जनजाति वर्ग के 41,146 विद्यार्थियों को 35 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। एनसीसी कैडेटों का कैंप मैसिंग भत्ता भी 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 के छह से बढ़कर अब 18 हो गई है।

मेडिकल शिक्षा का विस्तार, युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर

पिछले 12 वर्षों में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने 593 करोड़ रुपये की लागत से बने पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी और 844 करोड़ रुपये की लागत से बने महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल, कोरियावास, नारनौल का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद के अरुआ व दयालपुर, कैथल के घेरडू, कुरुक्षेत्र के खेड़ी रामनगर और पंचकूला के खेड़ावाली में 220 करोड़ रुपये की लागत से पांच नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर, 2024 से सभी नागरिक जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवा शुरू की गई है।

एचपीएससी ने एचसीएस भर्ती का अंतिम परिणाम किया घोषित

मेरिट, प्राथमिकता और श्रेणी के आधार पर 101 चयनित अभ्यर्थियों को मिले पद

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने शनिवार को हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। कुल 102 पदों के लिए 101 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अंतिम परिणाम में अभ्यर्थियों की मेरिट, उनकी ओर से दी गई प्राथमिकता और आरक्षण श्रेणी के आधार पर विभिन्न सेवाओं में पद आवंटित किए गए हैं।

इससे पहले आयोग ने आठ अक्टूबर को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की थी। उस परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर घोषित किए गए थे, जबकि उन्हें मिलने वाले पदों का विवरण अंतिम चरण में स्पष्ट किया गया।

आयोग के परिणाम के अनुसार, कुल 24 अभ्यर्थियों को हरियाणा



सिविल सेवा की कार्यकारी शाखा में स्थान मिला है। इनमें टॉपर अभिषेक सरोहा सहित आठ अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग से चयनित हुए हैं। कुलदीप, ईशा काला, क्रीमी, छवि, रजत फोगाट और मानवी को भी इस वर्ग में एचसीएस कैडर मिला है। वहीं, आरक्षित वर्ग के राहुल सैनी, रेणु और जैनव खातून भी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एचसीएस कैडर हासिल करने में सफल रहे।

जारी विवरण के अनुसार, आठ अभ्यर्थियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), 27 को उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी और दो को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के पद पर चयनित किया गया है। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के तीन पदों पर भी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

इसके अलावा जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी का एक, सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी के 22, यातायात प्रबंधक के सात, प्रथम श्रेणी तहसीलदार के तीन और प्रथम श्रेणी नायब तहसीलदार के पांच पदों के लिए आवंटन किया गया है। अंतिम परिणाम से अभ्यर्थियों को उनके आवंटित पदों की आधिकारिक जानकारी मिल गई है।

दिव्यांग कर्मचारी को 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति से राहत

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के 45 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी सतिंदर पाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बावजूद अगली सुनवाई तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।



◆ सतिंदर पाल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने सतिंदर पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत प्रदान की। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें 30 अक्टूबर, 2026 को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जाना था। याचिका में सेवानिवृत्ति के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया। दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर कानूनी विवाद पहले से चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित होने के बीच हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है। इससे सतिंदर पाल को फिलहाल अपनी नौकरी जारी रखने का अवसर मिलेगा। हालांकि, अदालत ने यह राहत अंतरिम रूप से दी है। मामले में अंतिम निर्णय अगली सुनवाई और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद लिया जाएगा।

पांच करोड़ की रंगदारी पर व्यापारियों का रोष, पुलिस को सोमवार तक अल्टीमेटम



पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की मांगी गिरफ्तारी

भारतेन्दु संवादाता, हिसार। पेट्रोलियम व्यवसायी प्रमोद गोयल, उनके भाई आनंद गोयल और बेटे अनिरुद्ध गोयल से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में व्यापारियों का रोष बढ़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हिसार और हांसी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एसपी सिद्धांत जैन से मुलाकात की। एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन को सोमवार तक ठोस कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार सलेमगढ़ ने कहा कि आनंद गोयल के परिवार को लगातार धमकियां मिलने की जानकारी सामने आ रही है। परिवार के सदस्यों और बच्चों को भी धमकाए जाने की बात गंभीर चिंता का विषय है। इससे व्यापारी वर्ग में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने पुलिस से मामले में तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की।

राजकुमार सलेमगढ़ ने कहा कि मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है। प्रतिनिधिमंडल ने एसपी के समक्ष अपनी चिंताएं रखीं। इस पर एसपी सिद्धांत जैन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

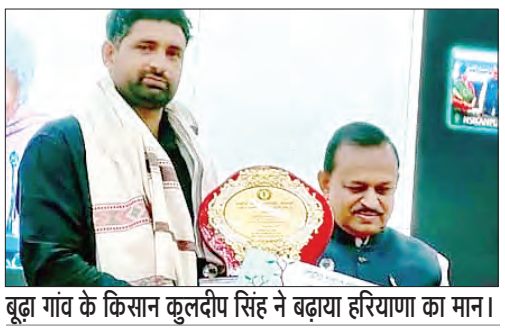
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि सोमवार तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर संगठन की दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आगे की रणनीति तय करने के साथ कड़ा फैसला लेने पर विचार किया जाएगा।

लाडवा के किसान कुलदीप सिंह ने गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार से पाया राष्ट्रीय सम्मान

एक हेक्टेयर में 1365 क्विंटल गन्ना उगाकर कुलदीप सिंह ने रचा इतिहास

भारतेन्दु संवादाता, लाडवा। मेहनत, लगन और आधुनिक कृषि तकनीकों के दम पर खेती को नई दिशा देने वाले लाडवा खंड के गांव बूढ़ा के प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ने क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की ओर से उन्हें गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के दो किसानों सहित देशभर से चयनित 13 प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

कुलदीप सिंह को यह सम्मान नई कृषि तकनीकों



बूढ़ा गांव के किसान कुलदीप सिंह ने बढ़ाया हरियाणा का मान।

और मशीनों का इस्तेमाल करके गन्ने की बेहतर पैदावार लेने के लिए दिया गया। उन्होंने सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर के सहयोग से प्रति हेक्टेयर 1365 क्विंटल गन्ने का उत्पादन हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें कानपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद रमेश अवस्थी और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की निदेशक सीमा ने सम्मानित किया।

कुलदीप सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रति एकड़ लगभग 500 से 550 क्विंटल तक गन्ने की पैदावार ले रहे हैं। उनका मानना है कि खेती में आधुनिक तकनीकों और मशीनों का सही इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाने के साथ मेहनत और लागत को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए समय पर कृषि कार्य करना, फसल की जरूरतों को समझना और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना जरूरी है।

उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीकों का समन्वय करने और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेने की अपील की। उनका कहना है कि आधुनिक कृषि पद्धतियां किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

नूंह के किसानों को हरी प्याज के मिल रहे बेहतर दाम

भारतेन्दु संवादाता, नूंह। नूंह जिले के किसानों को अगेती हरी प्याज की फसल से बेहतर कमाई हो रही है। पिनगवां खंड के खानपुर घाटी, रहपुआ और झिमरावट सहित आसपास के गांवों में उगाई गई हरी प्याज दिल्ली-एनसीआर की मंडियों में अच्छी कीमत पर बिक रही है। किसान सूखी प्याज तैयार होने का इंतजार करने के बजाय पत्तियों सहित हरी प्याज बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त कर रहे हैं। खानपुर घाटी के किसान इनायत ने बताया कि उन्होंने इस बार करीब पौने दो एकड़ में प्याज की खेती की है। वह सुबह खेत से प्याज उखाड़कर उसकी सफाई और छंटाई करते हैं तथा पिकअप के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम की मंडियों में पहुंचाते हैं। वहां हरी प्याज 40 से 50 रुपये प्रति किलो के थोक भाव पर बिक रही है। गुरुग्राम की मंडी में इसके भाव 35 से 45 रुपये प्रति किलो तक बताए जा रहे हैं। जिले में इस बार करीब 7700 हेक्टेयर भूमि पर हरी प्याज की खेती की गई है। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रजाक के अनुसार, अच्छे भाव मिलने से किसानों को लाभ हो रहा है। किसानों को उम्मीद है कि अगेती फसल से लागत निकालने के बाद शेष फसल से भी अच्छी कमाई होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

हरियाणा में 40 पार अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादले में मिलेंगे 10 अतिरिक्त अंक

नेता प्रतिपक्ष ने इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को शिक्षक तबादला नीति-2026 के तहत अब 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नीति को चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि पात्र अविवाहित शिक्षिकाओं को विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं की तरह तबादले में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके लिए नीति में संशोधन किया जाएगा, ताकि संबंधित शिक्षिकाओं को इस लाभ की जानकारी मिल सके और वे इसके लिए दावा कर सकें।



हरियाणा की पीजीटी शिक्षिका सूर्या मौदगिल सहित अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता सरदविंदर गोयल के माध्यम से शिक्षक तबादला नीति-2026 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति थी कि नीति में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को अतिरिक्त अंक देने का प्रविधान नहीं किया गया है, जबकि विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं और एकल अभिभावकों को यह लाभ दिया जा रहा है।

याचिका में तर्क दिया गया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 15 का दिया हवाला

ऐसे में उन्हें तबादले में अतिरिक्त अंकों के लाभ से बाहर रखना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने नीति में किए गए इस अंतर को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अविवाहित शिक्षिकाओं को केवल उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए कहा कि यह महिलाओं के लिए विशेष प्रविधान करने की अनुमति देता है। सरकार के निर्णय से पात्र शिक्षिकाओं को तबादले में अतिरिक्त अंक मिलने का रास्ता साफ होगा।

पंचकूला में दशहरे से पहले 20 लाख रुपए लेकर कारीगर फरार

शालीमार ग्राउंड में 221 फीट का रावण, परेड ग्राउंड में तैयारियां अधूरी

भारतेन्दु संवादाता, पंचकूला। शहर में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सेक्टर-5 के परेड ग्राउंड में पुतले बनाने का काम अधूरा रहने से आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। आयोजकों का आरोप है कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का जिम्मा संभालने वाला कारीगर उस्मान कुरैशी 20 लाख रुपये लेकर फरार हो गया है। कारीगर के अचानक लापता होने से दशहरा आयोजन की तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, परेड ग्राउंड में दशहरा उत्सव के लिए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तैयार

◆ रामलीला क्लब की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

किए जा रहे थे। आयोजन से पहले इन पुतलों का निर्माण पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हो सका। इसी बीच कारीगर उस्मान कुरैशी के कथित तौर पर लापता होने की जानकारी सामने आई। आयोजकों ने उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इसके बाद मामले की शिकायत रामलीला क्लब की ओर से पुलिस को दी गई।

शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

दशहरा आयोजन से पहले तैयारियां अधूरी

वहीं, शहर के शालीमार ग्राउंड में दशहरा उत्सव के लिए 221 फीट ऊंचे रावण का पुतला खड़ा करने की तैयारी है। दूसरी ओर, परेड ग्राउंड में पुतलों का निर्माण अधूरा रहने से आयोजन की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। आयोजकों को अब पुतलों के निर्माण और दशहरा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आगे की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

राहत रासायनिक खाद का विकल्प बनेगी वर्मीकंपोस्ट, सरकार देगी 80 प्रतिशत अनुदान

हरियाणा में जैविक खाद पर किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रदेश में किसानों को जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो और खेती को लंबे समय तक लाभकारी बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को जैविक खाद यानी वर्मीकंपोस्ट खरीदने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को खाद की कुल कीमत का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही अपनी जेब से



नायब सरकार का फैसला, जैविक खाद की खरीद पर भारी छूट।

खर्च करना होगा, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से वहन की जाएगी।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता से बाहर निकालकर खेती के प्राकृतिक विकल्पों की ओर प्रेरित करना है। मौजूदा समय में बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए कई किसान यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से अधिक इस्तेमाल करते हैं। इससे तत्काल फसल की वृद्धि में मदद मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक असंतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां प्रभावित होने के साथ उसकी प्राकृतिक संरचना और जल धारण करने की क्षमता भी कमजोर हो सकती है। ऐसी स्थिति में भूमि की उत्पादकता बनाए रखना किसानों के लिए चुनौती बन जाता है।

वर्मीकंपोस्ट जैविक खाद का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे केंचुओं की सहायता से जैविक अपशिष्ट पदार्थों के विघटन के जरिए तैयार किया जाता है।

टिकाऊ खेती को मिलेगा बढ़ावा

किसानों को खाद की खरीद पर 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने से जैविक विकल्प अपनाने की शुरुआती लागत कम हो सकती है। सामान्य तौर पर किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ऐसे में सरकारी अनुदान उन्हें जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक एकड़ खेत के लिए जैविक खाद उपलब्ध कराने की योजना से किसानों को इस विकल्प को अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस पहल की सफलता के लिए जरूरी होगा कि किसानों को जैविक खाद की गुणवत्ता, उचित मात्रा और इस्तेमाल के सही तरीके की जानकारी भी दी जाए। साथ ही, खाद की उपलब्धता और सब्सिडी का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचना चाहिए। मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने से भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

ट्रैफिक चालान वालों के लिए जरूरी खबर, 19 अक्टूबर से डाउनलोड करें लोक अदालत का टोकन

दिल्ली में 7 अदालतों में लगेगी लोक अदालत, 30 जून 2026 तक के चालानों पर होगी सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली वासियों के लिए लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे का अच्छा मौका आने वाला है। दिल्ली में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिक अपने पुराने और समझौते योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसकी जानकारी दी गई है।

लोक अदालत का आयोजन राजधानी के सात जिला न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। **30 जून 2026 तक के चालानों पर होगी सुनवाई** दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जारी नोटिस के मुताबिक, लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के लंबित समझौते योग्य यानी कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों और नोटिसों पर सुनवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में जारी किए गए चालान इस लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे। वाहन मालिकों को ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक चालान का निपटारा संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। सभी प्रकार के चालान अपने आप माफ नहीं होंगे। इसलिए लोक अदालत में जाने से पहले यह जांच करना जरूरी है कि उनका चालान सुनवाई के योग्य है या नहीं।


नेशनल लोक अदालत 25 अक्टूबर को लगने जा रही है।

लोक अदालत में चालान के निपटारे के लिए वाहन मालिकों को पहले टोकन या चालान की निर्धारित पर्ची डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। टोकन की संख्या सीमित रखी गई है। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय पर पोर्टल पर जाकर अपना टोकन डाउनलोड कर लें। बिना टोकन के लोक अदालत में चालान के निपटारे की सुनवाई नहीं हो सकेगी। टोकन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें संबंधित अदालत का नंबर और मजिस्ट्रेट की जानकारी दी जाएगी। इसी के आधार पर वाहन मालिक अपनी सुनवाई के लिए निर्धारित अदालत में पहुंच सकेंगे। लोक अदालत में पहुंचने से पहले वाहन मालिक सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इनमें वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), संबंधित ट्रैफिक चालान या नोटिस और आधार कार्ड शामिल हैं। दस्तावेज पूरे होने से सुनवाई के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

वाहन मालिकों को अपने चालान की जानकारी और टोकन पर दर्ज विवरण भी पहले से जांच लेना चाहिए।राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में किया जाएगा।

नवरात्र के सातवें दिन दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भीड़, कालकाजी में 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन

एजेंसी ,नई दिल्ली

शारदीय नवरात्र के सातवें दिन शनिवार को दक्षिणी दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। माथे पर लाल चुनरी, हाथों में पूजा की थाली और जुबां पर माता रानी के जयकारों के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। मंदिरों में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। **मां कालरात्रि की पूजा के लिए उमड़े भक्त**

नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों को भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती हैं। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और माता रानी के चरणों



में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की। कोई परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचा तो कोई घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दिन चढ़ने के साथ बढ़ता गया।

देर शाम तक मंदिरों में भक्तों की चहल-पहल बनी रही। दक्षिणी दिल्ली स्थित प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार, नवरात्र के शुरुआती सात दिनों में ही 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में माता रानी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए कतारें लगी रहीं।

श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता के जयकारे लगाते नजर आए। मंदिर में पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियों के चलते पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा।

आगरा में 500 से अधिक बंदरों के झुंड, आतंक रोकने के लिए बनेगी खास रणनीति

एजेंसी ,नई दिल्ली

आगरा में बंदरों के बढ़ते उत्पात से लोगों को निजात दिलाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ), देहरादून एक नई कार्ययोजना तैयार करेगा। इस योजना में पहली बार बंदरों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए अपनाए जा रहे पुराने तरीके प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं।

दरअसल, वन विभाग और नगर निगम की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरों का इस्तेमाल किया जाता है। पिंजरों में खाने का सामान रखकर बंदरों को आकर्षित किया जाता है। हालांकि, इस तरीके से कुछ बंदर ही पकड़े जाते हैं, जबकि बाकी बंदर भाग निकलते हैं। इससे शहर में बंदरों के बढ़ते उत्पात पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

इसी समस्या को देखते हुए अब भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की मदद से नई कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसमें बंदरों को पकड़ने के लिए तकनीकी उपायों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक, आगरा शहर में बंदरों के 500 से अधिक झुंड हैं।

ग्रेटर नोएडा में एक परिवार खत्म! घर में मृत मिले पांच सदस्य, जांच में जुटी पुलिस

एजेंसी ,नई दिल्ली



ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीगोपाल गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार सुबह जब ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले, तो महेश के परिवार के सभी पांच सदस्यों की मौत की खबर सामने आई। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी।

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने रात में आखिरी बार मैगी खाई थी। इसके बाद सुबह परिवार के पांचों सदस्य मृत पाए गए। हालांकि, मैगी खाने और मौतों के बीच क्या संबंध है, यह जांच का विषय है। घटना के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या यह घटना किसी हादसे का परिणाम है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। परिवार के पांच सदस्यों की एक साथ मौत ने ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौतों के कारणों का पता लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल, मामले में मौतों की वास्तविक वजह और घटनाक्रम से जुड़ी परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

दिल्ली में 80 लाख की हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, पहले करती थी शराब तस्करी

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली के शाहदरा जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित महिला के कब्जे से 200 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि महिला पहले शराब की तस्करी में शामिल थी, लेकिन अधिक कमाई के लालच में उसने हेरोइन बेचने का काम शुरू कर दिया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला की पहचान 39 वर्षीय सोनिया के रूप में हुई है।

एएनटीएफ की टीम को मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में जानकारी मिली थी। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से



प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

200 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी और मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है।

पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनिया पहले शराब की तस्करी करती थी। उसके खिलाफ शराब तस्करी से जुड़े तीन मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, महिला ने अधिक पैसे कमाने के उद्देश्य से हेरोइन की बिक्री शुरू कर दी थी। वह नशीले पदार्थ को छोटी-छोटी पुड़ियों में बांटकर ग्राहकों को बेचती थी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि महिला कब से हेरोइन की तस्करी में सक्रिय थी और उसके संपर्क किन-किन लोगों से थे। पुलिस को आशंका है कि इस कारोबार के पीछे अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने महिला से पूछताछ के आधार पर उसके कथित सप्लायर की पहचान कर ली है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हेरोइन की आपूर्ति कहां से की जाती थी और इसे किन इलाकों में बेचा जाता था।

सोनीपत के मरीजों को बड़ी राहत, अस्पताल में शुरू होगी डिजिटल भुगतान व्यवस्था

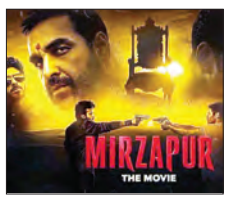
एजेंसी, नई दिल्ली

सोनीपत के जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को जल्द ही नकद भुगतान के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। अस्पताल में सभी प्रकार के लेनदेन को कैशलेस बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभिन्न भुगतान काउंटरों पर जल्द ही क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मरीज डिजिटल माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत ओपीडी की पांच रुपये की पर्ची बनवाने से लेकर एमएलआर फीस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। मरीजों को अब खुले पैसे रखने या चिल्लर की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान किया जा सकेगा। अस्पताल प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, 'मिर्जापुर: द मूवी' के निर्माता सेना कल्याण कोष में देंगे 50 हजार रुपये

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 'मिर्जापुर: द मूवी' के निर्माताओं को गाने 'शूरवीर' के कथित दुरुपयोग के मामले में आर्मी वेलफेयर फंड में 50,000 रुपये दान करने का निर्देश दिया है। यह गाना महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। मामले के अनुसार, फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस में 'शूरवीर' गाने का इस्तेमाल पृष्ठभूमि संगीत के रूप में किया गया था। इस इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को आर्मी वेलफेयर फंड में 50 हजार रुपये जमा कराने को कहा है। यह निर्देश गाने के इस्तेमाल से जुड़े विवाद के संदर्भ में दिया गया। 'मिर्जापुर' अपने अपराध और एक्शन आधारित कथानक के लिए चर्चित है। वहीं, 'शूरवीर' गाने को महाराणा प्रताप के सम्मान और वीरता से जोड़कर देखा जाता है। इस मामले ने फिल्मों में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को समर्पित गीतों के इस्तेमाल और उनकी प्रस्तुति को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।



नोएडा जिला अस्पताल के डॉ. अजय राणा पदोन्नत, आगरा में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

एजेंसी, नई दिल्ली। नोएडा जिला अस्पताल में स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे डॉ. अजय राणा को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने उन्हें अपर निदेशक पद पर पदोन्नत करते हुए आगरा जिला अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक नियुक्त किया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग की सचिव रितु माहेश्वरी ने प्रदेश के 31 चिकित्साधिकारियों की सूची जारी की। आदेश में सभी चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. अजय राणा नोएडा जिला अस्पताल में पिछले साढ़े चार वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। जून 2025 में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रेनू अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 30 जून को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाली थी। अब पदोन्नति के बाद उन्हें आगरा जिला अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।


स्त्री रोग एवं प्रसूता विशेषज्ञ डॉ. अजय राणा।

नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में प्रवेश का एक और मौका, 22 अक्टूबर तक करें आवेदन

एजेंसी ,नई दिल्ली

नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 22 अक्टूबर तक लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (एलईएसटी-2027) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन विद्यार्थियों को एक और अवसर मिला है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

22 अक्टूबर तक निशुल्क आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी गई है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर


सांकेतिक तस्वीर।

सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निशुल्क रखी गई है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म में गलती सुधारने का भी अवसर दिया जाएगा। इसके लिए समिति 23 से 25 अक्टूबर तक सुधार विंडो खोलेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने आवेदन में निर्धारित विवरणों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन से पहले पात्रता संबंधी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।

अब 90 प्रतिशत तक पैदा होंगी मादा बछिया! पशुपालकों को मिली नई तकनीक की सौगात

एजेंसी ,नई दिल्ली

पशुपालन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में एक नई उम्मीद जगी है। अब सेक्स-सार्टेड सीमेन तकनीक के जरिए लगभग 90 प्रतिशत तक मादा बछिया पैदा होने की संभावना रहेगी। इससे डेयरी व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को भविष्य में बेहतर दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुधन के विकास में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तकनीक से मादा बछिया होने की शत-प्रतिशत गारंटी नहीं है। पशुपालन विभाग की ओर से मेरठ स्थित विकास भवन सभागार में सेक्स-सार्टेड सीमेन तकनीक को लेकर एक दिवसीय मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पशु चिकित्सकों और संबंधित कर्मचारियों को इस आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और पशु चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों को इसके प्रति जागरूक करना था।

प्रयागराज में चलती कार बनी आग का गोला, चारों ने कूदकर बचाई जान

एजेंसी ,नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यमुनापार के नैनी क्षेत्र में लेप्रोसी चौराहे के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वाहन में सवार चार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को रोका और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ गांव निवासी मुकेश मिश्रा शुक्रवार सुबह अपनी दादी के अस्थि कलश का विसर्जन करने प्रयागराज आए थे। उनके साथ तीन अन्य लोग भी मौजूद थे। सभी ने


यमुनापार में चलते वाहन में लगी भीषण आग।

संगम पर अस्थि विसर्जन और पूजन-अर्चन किया। इसके बाद देर रात चारों कार से वापस मध्य प्रदेश लौट रहे थे। बताया गया कि कार मुकेश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा के नाम पर पंजीकृत थी।

चारों लोग प्रयागराज से अपने घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक उनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई। यमुना नदी पर बने नए पुल को पार करने के बाद अचानक कार से धुआं निकलने लगा। स्थिति को भांपते हुए कार सवार लोगों ने वाहन रोक दिया और तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वाहन धू-धूकर जलने लगा। कार में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी।

98 सेंटीमीटर कद, 22 किलो वजन... 44 साल की महिला की एम्स में सफल सर्जरी

एजेंसी, नई दिल्ली



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टरों की टीम ने महज 98 सेंटीमीटर कद और 22 किलोग्राम वजन वाली 44 वर्षीय महिला का गर्भाशय कीहोल सर्जरी के जरिए निकाल दिया। यह पूरी सर्जरी लगभग 90 मिनट में पूरी हुई। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत में सुधार हुआ और उसे तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार, महिला पिछले एक साल से मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द से परेशान थी।

चिकित्सकीय जांच में पता चला कि उसके गर्भाशय के बाहर और गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं मौजूद थीं। इस स्थिति के कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। महिला की शारीरिक स्थिति के कारण यह ऑपरेशन डॉक्टरों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। उसका कद लगभग चार साल के बच्चे जितना था और वजन भी काफी कम था। इसके अलावा, वह गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित थी।

इस बीमारी में हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे चोट या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। महिला को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी थी। एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर रीता माहे और डॉ. स्वाति तोमर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने यह सर्जरी की। तमाम चिकित्सकीय चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद ऑपरेशन सफल रहा।

दिल्ली में दुर्गा पूजा का असर, 8 प्रमुख सड़कों पर बढ़ेगा ट्रैफिक; 20 अक्टूबर तक रहें सतर्क

दुर्गा पूजा के लिए चितरंजन पार्क और ग्रेटर कैलाश-2 जाने वालों के लिए जरूरी सूचना

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के दक्षिणी इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के चलते अगले कुछ दिनों तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। चितरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश-2 (जीके-2) में आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा समारोहों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे इन इलाकों से गुजरने से पहले यातायात की स्थिति की जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

दक्षिणी दिल्ली के चितरंजन पार्क और ग्रेटर कैलाश-2 में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। पूजा पंडालों में दर्शन, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने


दिल्ली में अगले कुछ दिन प्रमुख रास्तों पर लग सकता है जाम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता

से आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। यातायात पुलिस के अनुसार, इन समारोहों के कारण दोनों क्षेत्रों के आसपास की आठ प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित की जा सकती है, जबकि भीड़ बढ़ने की स्थिति में यातायात को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा जा सकता है। दुर्गा पूजा समारोहों के मद्देनजर वाहन चालकों को 20 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

खासकर सीआर पार्क और जीके-2 की ओर जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने को कहा गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और पूजा पंडालों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। इससे यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा से बचने में मदद मिल सकती है। यातायात प्रभावित होने की स्थिति में पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। वाहन चालकों को सड़क पर लगे यातायात संकेतों और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। साथ ही, अनावश्यक रूप से पूजा पंडालों के आसपास वाहन खड़ा करने से बचना चाहिए, ताकि यातायात सुचारु बना रहे।

ग्रेटर नोएडा में किसान को गलती से मिला दूसरे की जमीन का मुआवजा, अब 13 लाख रुपये भी लौटाने होंगे

एजेंसी ,नई दिल्ली

जमीन के मुआवजा वितरण में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यीडा क्षेत्र के गुनपुरा गांव में प्रशासन ने गलती से एक किसान को दूसरे किसान की जमीन का मूल मुआवजा दे दिया था। अब मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है कि संबंधित किसान ने जमीन के मूल मुआवजे के अलावा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के रूप में करीब 13 लाख रुपये भी प्राप्त किए थे। प्रशासन अब किसान से मूल मुआवजे के साथ अतिरिक्त राशि भी वापस लेने की तैयारी कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा वितरित करते समय हुई गलती के कारण दूसरे किसान की जमीन की मुआवजा राशि गलत व्यक्ति के खाते में चली गई। इसके बाद संबंधित किसान ने प्राधिकरण से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की रकम भी हासिल कर ली। अब इस मामले में प्रशासन ने राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है।प्रशासन के सामने मामला आने के बाद अब गलत तरीके से भुगतान की गई राशि वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें जमीन का मूल मुआवजा और अतिरिक्त मुआवजे के रूप में प्राप्त करीब 13 लाख रुपये, दोनों शामिल होंगे।

वसूली के बाद यह रकम जमीन के वास्तविक हकदार किसान को दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी।गुनपुरा गांव का यह मामला जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। गलत व्यक्ति को मूल मुआवजा मिलने के बाद अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान होना भी जांच का विषय है। अब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वसूली की कार्रवाई नियमानुसार पूरी हो और वास्तविक जमीन मालिक को उसका हक मिल सके।

मसूरी में सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर सख्त हुआ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग



भारतेन्दु संवादाता, सुनील सोनकर

21 विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी, पीएफ की जांच और पढ़े-लिखे कर्मचारियों को लिपिक पद पर तैनात करने के निर्देश

मसूरी। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मसूरी नगर पालिका के टाउन हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गौरव ने 21 विभागों की बैठक में अधिकांश अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशासी अधिकारी और नायब तहसीलदार को अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने की संस्तुति की जाएगी। बैठक में उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने नगर पालिका में ठेका प्रथा के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य सुविधाओं की जांच कराने को कहा, ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने शिक्षित पर्यावरण मित्रों की योग्यता के अनुसार लिपिक पदों पर तैनाती की संभावनाएं तलाशने और 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। संतोष गौरव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उचित वेतन, निर्धारित सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए। उनके वेतन और श्रम कानूनों के अनुपालन से जुड़े मामलों को शासन के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने वाल्मीकि बस्ती में शिविर लगाकर कर्मचारियों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्र शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके कल्याण और अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बैठक में नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा, एसएसआई सतेंद्र भाटी, अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

उत्तराखंड को प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्र बनाना प्राथमिकता : धामी

बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग से राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही उत्तराखंड की पहचान

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय भू-दृश्यों और सांस्कृतिक विरासत के कारण बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। इन दिनों राज्य में कई बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग चल रही है। अभिनेता अक्षय कुमार मसूरी और लैंढौर क्षेत्र में, जबकि अभिनेत्री जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर रही हैं। इससे उत्तराखंड की फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में पहचान मजबूत होने के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुमति प्रक्रिया सरल बनाने और स्थानीय कलाकारों व तकनीशियनों को अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है।



उत्तराखंड बना फिल्म निर्माताओं की पसंद

अभिनेता अक्षय कुमार मसूरी और लैंढौर क्षेत्र में, जबकि जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर रही हैं। बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स के आगमन से राज्य की पहचान मजबूत होने के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे प्रमुख फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुमति प्रक्रिया सरल बनाने और स्थानीय कलाकारों व तकनीशियनों को अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है।

फिल्म नीति से आसान होगी शूटिंग

राज्य सरकार उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के तहत फिल्म निर्माण के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। एकल खिड़की अनुमति व्यवस्था के माध्यम से शूटिंग की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्धारित व्यवस्था के तहत सात दिनों में अनुमति उपलब्ध कराने पर जोर है।

फिल्म शूटिंग से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री के अनुसार, फिल्म शूटिंग से स्थानीय युवाओं, कलाकारों, होटल व्यवसायियों, परिवहन संचालकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। मसूरी, लैंढौर और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की संभावना है। सरकार फिल्म पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

ऑडियो में छेड़छाड़ नहीं, पुलिस जांच पर भरोसा : रेखा आर्य

भारतेन्दु संवादाता, देहरादून

उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को दावा किया कि उनकी ओर से सार्वजनिक किया गया ऑडियो पूरी तरह असली है और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज है और उन्हें उत्तराखंड पुलिस की निष्पक्ष जांच पर भरोसा है।

कैबिनेट मंत्री आर्य आज अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में अपने पति से जुड़े विवाद, सार्वजनिक किए गए ऑडियो और अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके पति के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने के बाद उनके मन में सवाल उठने लगे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद पड़ताल करने पर संबंधित ऑडियो सामने आई। उन्होंने कहा कि ऑडियो सुनने के बाद उन्हें लगा कि यह मामला लोगों के सामने आना चाहिए, ताकि सभी को पता चल सके कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति किस तरह की बातें कर रहा है।

मंत्री आर्य ने कहा कि उन्होंने अपने पति के साथ 22-23 साल के संबंधों में पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। ऐसे में ऑडियो में कथित तौर पर उनके प्रति की गई टिप्पणियों और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का समर्थन किए जाने की बात सामने आने पर उन्होंने इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया।



कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि घरेलू हिंसा या किसी भी तरह के अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज की प्रतिक्रिया की चिंता छोड़कर अपने आत्मसम्मान और बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तीन बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुकी हैं। इसके बावजूद इस मामले को सार्वजनिक करने पर उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए अपनी बात रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह अपने पास समस्याएं लेकर आने वाली महिलाओं को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह देती हैं।

न्यूज ब्रीफ

पौड़ी रामलीला में शूर्पणखा के अभिनय ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

भारतेन्दु संवादाता, पौड़ी। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला के छठवें दिन कलाकारों ने शानदार अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। कशिश ने सुपर्णखा के किरदार में अभिनय और नृत्य से विशेष छाप छोड़ी। उनकी प्रस्तुति पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। इस दौरान कैकई-भरत संवाद, भरत का चित्रकूट प्रस्थान, अत्रि मुनि और माता अनसूया से भेंट, सुपर्णखा की नाक कटने तथा खर-दूषण वध तक की लीला का मंचन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पौड़ी रामलीला समिति की दूसरी स्मारिका 'नमामि रामम्' का लोकार्पण भी किया गया। इसमें रामलीला के पिछले 12 वर्षों के इतिहास को समेटा गया है।

राज्य आंदोलनकारियों के हाथों में संविधान संशोधन की जिम्मेदारी



भारतेन्दु संवादाता, देहरादून। संविधान संशोधन समिति में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनुभवी और साफ-सुथरी छवि के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया है। समिति में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, किसान नेताओं और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उम्मीद जताई गई है कि समिति पार्टी के विश्वास पर खरी उतरेगी और संविधान संशोधन से जुड़े दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगी। समिति में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी गीता बिष्ट, रविंद्र वशिष्ठ और सलीम अहमद को स्थान दिया गया है। इनके अलावा दिनेश भट्ट, पत्रकार देवेंद्र चमोली, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश बिंजोला, हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिनेश नेगी, प्रोफेसर डॉ. गोविंद सिंह रावत, किसान नेता राकेश चौहान, पूर्व सैनिक अधिकारी देवचंद उत्तराखंडी और शिव सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार अनिल थपलियाल तथा इंजीनियर महेंद्र सिंह को मनोनीत किया गया है। वाचस्पति भट्ट सलाणी को पदेन सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि डॉ. शक्तिशैल कपरवाण समिति के संरक्षक होंगे। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों की भागीदारी से संविधान संशोधन संबंधी विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श और सुझावों को महत्व मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड की श्रमिक स्वास्थ्य योजना का अध्ययन करेगी यूपी टीम

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (सीएमएसएसवाई) दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है। इसी क्रम में शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य श्रम विभाग के अपर श्रम आयुक्त जुनैद के नेतृत्व में पहुंची टीम ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना की कार्यप्रणाली को समझा। टीम ने योजना की रूपरेखा, तकनीकी व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य जांच सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

उत्तराखंड के श्रमायुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर जरूरत के अनुसार चिकित्सा परामर्श और उपचार के लिए रेफरल सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बिना किसी पूंजीगत निवेश के अब तक लगभग 60 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा चुकी है।

भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश की टीम ने स्वास्थ्य जांच शिविरों के संचालन, जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया।



श्रमिकों की सेहत पर उत्तराखंड का जोर

उत्तराखंड के श्रमायुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर जरूरत के अनुसार चिकित्सा परामर्श और उपचार के लिए रेफरल सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बिना किसी पूंजीगत निवेश के अब तक लगभग 60 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा चुकी है। टीम ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के व्यापारियों को मिलेगी बीमा सुरक्षा

भारतेन्दु संवादाता, देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को एक वर्ष तक आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से योजना के संचालन के लिए 19 नवंबर 2026 से 18 नवंबर 2027 तक की अवधि के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में सचिव, उत्तराखंड शासन रणवीर सिंह चौहान ने आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखंड को पत्र भेजकर निर्णय की जानकारी दी है। योजना के विस्तार से राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसका उद्देश्य दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों में व्यापारियों को सहायता प्रदान करना और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य में व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में बीमा सहायता व्यापारियों और उनके परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है। शासन की ओर से योजना को आगे जारी रखने की स्वीकृति मिलने से पात्र व्यापारियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। राज्य कर विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। योजना की निरंतरता से व्यापारियों के हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा।

जयानंद भारती का जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की मिसाल : महाराज

कर्मवीर जयानंद भारती की 146वीं जयंती पर राजकीय मेले का शुभारंभ

अनिल थपलियाल



देहरादून। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्तराखंड रत्न कर्मवीर जयानंद भारती की 146वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को विकासखंड बीरोंखाल के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर, स्यूंसी में दो दिवसीय राजकीय मेले का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जयानंद भारती के संघर्ष, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया।

सतपाल महाराज ने कहा कि जयानंद भारती का जीवन त्याग, संघर्ष, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने ऐसे समय में समाज को नई दिशा देने का काम किया, जब देश अंग्रेजी शासन के अधीन था और समाज छुआछूत, जातिगत भेदभाव तथा अनेक कुरीतियों से जूझ रहा था।

जयानंद भारती के भवन का होगा जीर्णोद्धार

महाराज ने कहा कि जयानंद भारती का ऐतिहासिक डोला-पालकी आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उस समय समाज के कुछ वर्गों को विवाह जैसे अवसरों पर डोला-पालकी के इस्तेमाल तक के अधिकार से वंचित रखा जाता था। भारती ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों की पैरवी की। उन्होंने बताया कि भारती ने ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड मैलकम हेली के सामने तिरंगा फहराकर और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाकर भी साहस का परिचय दिया था। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐतिहासिक धरोहरों और महान विभूतियों की स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जयानंद भारती के जर्जर भवन के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया गया है, जिस पर उन्होंने सहमति दी है।

नवरात्रि नारी शक्ति और आस्था का प्रतीक : धामी

अनिल थपलियाल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में मातृ शक्ति का विशेष एवं पूजनीय स्थान है। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व समाज को मातृ शक्ति के सम्मान, सामर्थ्य और महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं देश की समृद्ध विरासत की पहचान हैं।

धामी ने कहा कि हमारे त्योहार सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के साथ समाज में आस्था, सद्भाव और एकता की भावना को भी सशक्त बनाते हैं। ऐसे पर्व हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि इन परंपराओं और मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, ताकि सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता बनी रहे।

देहरादून में फायरिंग, बेखौफ अपराधी? पटेलनगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पीसीआर पर लिया

विकास बलूनी

अभियुक्त की निशानदेही पर नया गांव क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त तमंचा व जिंदा कारतूस किये बरामद

देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में फायरिंग कर युवक को घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित गुरमीत को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 32 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने यह बरामदगी नया गांव क्षेत्र के जंगलों से की है। आरोपित मूल रूप से सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है।

पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को स्विफ्ट कार सवार युवकों ने पटेलनगर क्षेत्र में फायरिंग की थी। इस दौरान एक युवक साहिल गोली लगने से घायल हो गया था। मामले में कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान आरोपित रोहित को घटना में प्रयुक्त कार के साथ नया गांव बैरियर से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे आरोपित नमन को 24 सितंबर को शामली से पकड़ा गया था। मुख्य आरोपित गुरमीत की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसके बाद उसने तीन अक्टूबर को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने पूछताछ और असलहा बरामदगी के लिए न्यायालय से उसका रिमांड प्राप्त किया।





एसएसपी देहरादून।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसका आदित्य और उसके साथियों के साथ पहले से विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ आईटीएस कॉलेज रोड पर उन पर फायरिंग की थी। वहां से भागने के बाद पीछा किए जाने पर शिमला बाईपास रोड स्थित सेंट ज्यूड्स चौक के पास दोबारा गोली चलाई गई, जिसमें साहिल घायल हो गया था। घटना के बाद आरोपित पुलिस से बचने के लिए सहारनपुर और अन्य स्थानों पर चला गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपित के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड : नवरात्रि के पावन अवसर पर भी गूंज रही मां की पुकार, आखिर कब सुनेगी सरकार?

विकास बलूनी

देहरादून। एक माँ जब अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए, तो समझिए व्यवस्था से कहीं न कहीं गंभीर सवाल जुड़े हैं।

भारत देश माँ के त्याग, ममता और बलिदान की नींव पर खड़ा है। चाहे वह घर की माँ हो, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जीवन भर संघर्ष करती है, या भारत माँ, जिसकी अस्मिता और सम्मान के लिए देशवासी अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते हैं।

लेकिन जब एक माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय माँगने के वास्ते सड़कों पर उतरना पड़े, तो यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल बन जाता है। अंकिता भंडारी का मामला केवल एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक माँ की उस व्यवस्था से जंग है, जिसमें उसकी बेटी की जिंदगी छिन गई।



एआई निर्मित चित्र।

उस माँ की पीड़ा को समझना होगा, जिसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन न्याय की उम्मीद अब भी बाकी है। उसकी आवाज को अनसुना करना केवल एक माँ के दर्द की अनदेखी नहीं, बल्कि समाज के न्याय पर भरोसे को कमजोर करना है।

सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि जनता की न्याय की पुकार

यह लड़ाई केवल अंकिता भंडारी की नहीं है। यह एक माँ की सत्ता और व्यवस्था से लड़ाई है

को दबाया नहीं जा सकता। यदि किसी भी स्तर पर न्याय की राह में जानबूझकर बाधा डाली जाती है, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।

यह लड़ाई केवल अंकिता भंडारी की नहीं है। यह एक माँ की सत्ता और व्यवस्था से लड़ाई है—उस व्यवस्था से, जिसके सामने वह अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है।

याद रखिए, माँ की आह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्याय की माँग करने वालों की आवाज सुनना और निष्पक्ष जाँच व कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना सत्ता की जिम्मेदारी है। अंकिता को न्याय मिले—यही उस माँ की पुकार है और यही समाज की न्याय व्यवस्था से अपेक्षा होनी चाहिए।

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, देहरादून में रैली-प्रदर्शन से उठी न्याय की आवाज

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से आईएसबीटी तक निकाले गए इस प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ,हरक सिंह रावत सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी रही।

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है। वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए।

महिला सुरक्षा और अंकिता मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन

इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस उस समय फिर तेज हुई, जब दुष्यंत कुमार गौतम को हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने इस नियुक्ति के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन के दौरान सवाल उठाए और अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े आरोपों पर स्पष्टता की मांग की।



न्यूज ब्रीफ

सड़क पर मक्की की फसल बिछाकर रोका वाहनों का रास्ता, महिला सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस थाना बरमाणा के अंतर्गत खलोटा गांव को जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर मक्की की फसल रखकर रास्ता बाधित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नम्होल निवासी चैत राम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गांव की एक महिला और अन्य लोगों ने सार्वजनिक सड़क पर मक्की की फसल फैला दी, जिससे वाहनों और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, पुलिस थाना बरमाणा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत अभियोग दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है।

कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के दावे पर विपिन परमार का सवाल, पहले दें 10 गारंटियों का हिसाब

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले अपनी दस गारंटियों और विकास कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखे। परमार ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए बेहतर सड़कें, पार्किंग, पर्यटक सुविधाएं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जरूरी हैं। धर्मशाला में सम्मेलनों तथा होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लक्ष्यों पर उन्होंने सरकार से स्पष्ट कार्ययोजना बताने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में नई घोषणाओं के बजाय जनता को विकास के ठोस परिणाम चाहिए।

25 साल बाद बिलासपुर में लौटेगा रणजी ट्रॉफी का रोमांच, हिमाचल-मुंबई के बीच मुकाबला 18 से

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर में 25 साल बाद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले का रोमांच देखने को मिलेगा। 18 से 21 अक्तूबर तक लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश और मुंबई की टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। एचपीसीए ने मैच के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने मैदान में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। प्रशासन ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है।

घुमारवीं कॉलेज के रोवर्स एवं रेंजर्स ने बाबा बसंदी कुटिया तक पदयात्रा कर स्वच्छता का दिया संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की रोवर्स एवं रेंजर्स इकाई ने शनिवार को केटीधार स्थित बाबा बसंदी कुटिया तक एक दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन और सामाजिक सेवा की भावना विकसित करना रहा। पदयात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय से कुटिया तक लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद मार्ग और कुटिया परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई की तथा लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में इकाई के मार्गदर्शक डॉ. प्रवीण और प्रो. अनु शर्मा भी उपस्थित रहे।

रोजगार की संभावनाओं से रूबरू हुए विद्यार्थी

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पौंटा में रिटेल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए विशेष गेस्ट लेक्चर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट के रिटेल मैनेजमेंट शिक्षक राकेश कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को रिटेल इंडस्ट्री, ग्राहक सेवा, बिक्री कौशल और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बी.वॉक. डिग्री प्रोग्राम के लाभों से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में विद्यालय की रिटेल मैनेजमेंट शिक्षिका शिल्पा चोपड़ा और टूरिज्म शिक्षक अजय कुमार भवानी ने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त किया।

कैप्टन कंवर ने संभाली आर्मी अस्पताल की कमान

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। आर्मी अस्पताल सरकाघाट में रिक्त पड़े प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कैप्टन एके कंवर ने कार्यभार संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने पर सरकाघाट भूतपूर्व सैनिक लीग ने भव्य स्वागत किया। लीग अध्यक्ष कैप्टन प्यार चंद बनयाल ने उम्मीद जताई कि प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को दवाइयों की नियमित उपलब्धता तथा रेफरल सुविधा में राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी आशा जताई कि आर्मी अस्पताल की जमीन से जुड़ा लंबित मामला जल्द सुलझेगा। इस अवसर पर कैप्टन विनोद, कैप्टन रघुवीर सिंह, कैप्टन बलदेव राज, सूबेदार मेजर विजय कुमार और सूबेदार ज्ञानचंद उपस्थित रहे।

धौलरा मंदिर के शारदोत्सव में समर ने झटका प्रथम स्थान, डॉ. मल्लिका ने किया सम्मानित



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर के ऐतिहासिक धौलरा मंदिर में शारदोत्सव के तहत सप्तमी पर मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। पंडित सुधांशु शेखर भट्टाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान संपन्न करवाया। इस दौरान आयोजित वैदिक मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता में समर ने संपूर्ण गीता के श्लोक सुनाकर प्रथम स्थान हासिल किया। मनन द्वितीय और हर्षिका तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के निर्णायक आचार्य प्रशांत और आचार्य वरुण रहे। डॉ. मल्लिका नड्डा ने कलाकारों को सम्मानित किया। शाम को भजन गायक अभिषेक सोनी ने गुरु वंदना सहित अनेक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया।

नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर होगी लाइव निगरानी : डॉ. राजेश शर्मा

हिमाचल में नकल के मामलों में आई बड़ी कमी, 268 से घटकर 64 रह गए मामले

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शनिवार को कुल्लू के साई स्टार स्कूल, ढालपुर और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भुंतर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों, परीक्षा प्रणाली और नकल रोकने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर लाइव निगरानी और ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में नकल के 268 मामले सामने आए थे, जबकि इस बार इनकी संख्या घटकर 64 रह गई है। उन्होंने कहा कि जनसहयोग और लोगों से मिली सूचनाओं ने भी नकल रोकने में



◆ एनईपी-2020 के अनुरूप बदलेगा परीक्षा पैटर्न, रटने के बजाय समझ और तार्किक क्षमता पर रहेगा जोर

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्नपत्रों में प्रश्नों के क्रम और संख्या में बदलाव जैसे उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाया जा रहा है। प्रश्नपत्रों में अवधारणात्मक समझ, तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल पर आधारित प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाएगा। विद्यार्थियों की तैयारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्नपत्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और प्रामाणिक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने तथा अधिकृत स्रोतों से पुस्तकें खरीदने की सलाह दी।

शिक्षा के साथ संस्कार व नशामुक्ति पर जोर

डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। बोर्ड पाठ्यक्रम में हिमाचल की संस्कृति, देवी-देवताओं से जुड़ी परंपराओं और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। उन्होंने 'शिक्षा युक्त हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' की टैगलाइन का उल्लेख करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सहयोग से ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है।

पिकअप से 1 किलो 12 ग्राम चरस बरामद, मंडी के दो आरोपी गिरफ्तार



अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। पुलिस जिला नूरपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए नूरपुर की टीम ने 1 किलो 12 ग्राम चरस बरामद कर मंडी जिले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, रात्रि गश्त के दौरान एनएच-154 पर नूरपुर से पठानकोट की ओर जाने वाले मार्ग पर बौड़ बस स्टॉप के नजदीक सड़क किनारे पिकअप गाड़ी नंबर एचपी-76-2409 खड़ी मिली। तलाशी लेने पर चालक सीट के नीचे छिपाकर रखी गई चरस बरामद हुई। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों

◆ नशे के अवैध कारोबार पर नूरपुर पुलिस का शिकंजा, चालक सीट के नीचे छिपाई थी चरस

की पहचान किशोरी लाल (35) और उत्तम चंद (45), निवासी बड़ी बजगान, जिला मंडी, के रूप में हुई है।

पुलिस थाना नूरपुर में दोनों के खिलाफ मामला नंबर 263/2026, धारा 20 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है। पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

राम-भरत मिलाप से लेकर रावण दरबार तक के दृश्य देख भावविभोर हुए दर्शक



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। नगर परिषद मैदान कांगड़ा में आयोजित रामलीला की छठी संध्या में अग्रवाल क्रिएशन के मालिक विनोद अग्रवाल मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने रामलीला सभा को 11 हजार रुपये की राशि भेंट की। साथ ही पर्ची निकालकर 10 विजेताओं को आयोजकों की ओर से और दो विजेताओं को अपनी ओर से इनाम दिए।

विनोद अग्रवाल ने बंपर ड्रॉ के लिए 10 डबल बेड कंबल देने की घोषणा भी की, जिससे पुरस्कारों की संख्या बढ़ गई। छठी संध्या में राम-निषादराज

◆ कांगड़ा रामलीला की छठी संध्या में विनोद अग्रवाल ने की 11 हजार रुपए की भेंट

मिलाप, केवट द्वारा गंगा पार करवाना, भरत-राम मिलाप, पंचवटी गमन, शूर्पणखा की नाक काटने और रावण दरबार सहित कई प्रसंगों का मंचन किया गया। रामलीला देखने प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में रामलीला सभा के पदाधिकारी, निर्देशक और सदस्य मौजूद रहे। मंच संचालन अतुल चौधरी ने किया।

कोटली स्कूल में नशे के खिलाफ जगाई अलख

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली में 'युवा बचाओ अभियान' के तहत नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना रहा। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की सचिव सुनीता बिष्ट ने संतुलित आहार अपनाने और नशीले पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की सदर खंड इकाई सचिव विनय कुमारी ने समिति के कार्यों और अभियान की जानकारी दी। दया राम चौहान ने वीडियो के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव समझाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव ठाकुर ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में शिक्षक, समिति के सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कुल्लू दशहरा: ढालपुर चौक से कॉलेज गेट तक बदला ट्रैफिक रूट, कला केंद्र मार्ग रहेगा बंद

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश 17 अक्तूबर से 8 नवंबर तक विभिन्न चरणों में लागू रहेंगे। आदेश के अनुसार, ढालपुर चौक से कॉलेज गेट के बीच वाहनों की आवाजाही क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग से होगी, जबकि कला केंद्र मार्ग बंद रहेगा। फोरलेन से सरवरी जाने वाले वाहन अखाड़ा बाजार बेली ब्रिज अथवा भूतनाथ पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। 21 से 28 अक्टूबर तक

◆ 8 नवंबर तक बदलेगी यातायात व्यवस्था, 18 स्थानों पर मिलेगी 2 हजार वाहनों की पार्किंग सुविधा

लगवैली से आने वाले वाहनों को नए बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा।

प्रशासन ने 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक विभिन्न प्रमुख सड़कों पर नो-पार्किंग और टो-अवे प्रतिबंध भी लागू किया है। वहीं, कॉलेज गेट के समीप पशु मैदान में अस्थायी बस अड्डा संचालित होगा। दशहरा उत्सव के दौरान शहर में 18 स्थानों पर लगभग 2,000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इनमें वन विभाग मैदान, कैटल ग्राउंड, विपाशा मार्केट, सब्जी मंडी, डीएवी स्कूल मैदान मोहल और शांगरी बाग सहित अन्य स्थल शामिल हैं।

इसके अलावा, 20 से 28 अक्तूबर तक राइट बैंक पर भुंतर के सैनिक चौक से रामशिला स्थित गैमन पुल तक माल चढ़ाने-उतारने का समय रात 12 से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

कुल्लू के युवा कलाकार दशहरा उत्सव में बिखेरेंगे संस्कृति के रंग

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। सूत्रधार कला संगम की ओर से कुल्लू घाटी के बच्चों को लोक संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से 10 अक्टूबर 2026 से आयोजित लोक नृत्य कार्यशाला का समापन संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने कार्यशाला के दौरान सीखे लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। दिनेश सेन ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करेगी और कलाकारों को मंच प्रदान करेगी। कार्यशाला का निर्देशन संस्था के वरिष्ठ कलाकार एवं प्रचार-प्रसार प्रभारी सुंदर श्याम महंत ने किया। लोक नृत्य प्रभारी सीमा शर्मा और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत गुरु विद्या सागर शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में पलक, शबनम, कृतिका, वंशिका, गौरी, राहुल, आयुष, अक्षय और तरुण सभरवाल सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि सूत्रधार कला संगम दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में पंडित विद्या सागर के निर्देशन में तैयार कत्थक समूह नृत्य प्रस्तुत करेगा। साथ ही संस्था भाषा एवं संस्कृति विभाग की लोक नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। दिनेश सेन ने सभी कलाकारों को दशहरा उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

नगर निगम हमीरपुर ने निजी प्रोफेशनल्स को भवन निर्माण नियमों के पालन के दिए निर्देश

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा की अध्यक्षता में निजी प्रोफेशनल्स के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भवन निर्माण के नक्शों, भू-उपयोग और नियोजन संबंधी कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में निजी प्रोफेशनल्स को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 तथा लागू विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने को कहा गया। साथ ही, जहां लागू हो, अधिनियम के परिशिष्ट-1 में निर्धारित पात्रता, क्षेत्रफल और अन्य शर्तों का पालन करने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने भवन की ऊंचाई, सेटबैक, कवर्ड एरिया, एफएआर, पार्किंग व पहुंच मार्ग जैसे मानकों की जांच करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेजों और अन्य प्रमाणपत्रों की सत्यता सुनिश्चित की जाए। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम ने नागरिकों से भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां लेने और सभी लागू नियमों का पालन करने की अपील की।

टेट प्रभावित शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी करवाने की मांग



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव हितेंद्र साहसी ने की। इस दौरान प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करवाने की मांग उठाई गई।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक लंबे समय से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फेडरेशन ने शिक्षकों के अनुभव और वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का उचित समाधान करने का आग्रह किया। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कदम उठाने की दिशा में प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर टेट प्रभावित शिक्षक मोर्चा हिमाचल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरमेश लाल शर्मा सहित खेम दास महंत, कुसुम लता, दिनेश कुमार, मनोहर लाल शर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चेतना संस्थान ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। चेतना संस्थान बिलासपुर में शनिवार को स्पेशल ओलंपिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले विशेष खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की संस्थापिका एवं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्षा डॉ. मल्लिका नड्डा मुख्य अतिथि रहीं।

समारोह में अल्पाइन स्कीइंग के स्वर्ण पदक विजेता दीपक ठाकुर को 20 लाख रुपये और स्नोशूइंग की रजत पदक विजेता शालिनी चौहान को 14 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के लिए सम्मानित किया गया। अल्पाइन स्कीइंग में शिवांजलि और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले शुभम को भी सम्मान मिला। डॉ. मल्लिका नड्डा ने खिलाड़ियों को प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि उचित अवसर मिलने पर दिव्यांगजन भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। समारोह में संस्थान के सचिव हरीश नड्डा, निदेशक अरुण कुमार गौतम और प्रशासक कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

मजारी स्कूल में शहीद मुल्तान सिंह को दी श्रद्धांजलि, वीरांगना ऊषा की सम्मानित



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मजारी में शनिवार को विद्यालय के पूर्व छात्र एवं अमर शहीद हवलदार सरदार मुल्तान सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य सुरजीत ठाकुर, शिक्षकों, विद्यार्थियों और एसएमसी सदस्यों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को शहीद की वीरगाथा सुनाते हुए बताया कि 17 अक्तूबर 2004 को मणिपुर के इंफाल पश्चिम में छोटा बेकरा क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करते हुए मुल्तान सिंह ने तीन गोलियां लगने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया और देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की।

समारोह में शहीद की पत्नी ऊषा देवी को स्मृति चिह्न और माता की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद की बेटी प्रनीत कौर, एसएमसी अध्यक्ष गुरमैल सिंह सहित विद्यालय स्टाफ, पूर्व सैनिक और अभिभावक मौजूद रहे।

तृप्ता स्कूल चलवाड़ा में धूमधाम से मनाया नवरात्रि पर्व कन्या पूजन कर दिया नारी शक्ति के सम्मान का संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। तृप्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलवाड़ा में नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में किंडरगार्टन सेक्शन द्वारा विशेष पूजन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा, भक्ति, प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के चेयरमैन वरिंद्र नरियाल और प्रधानाचार्य राकेश राणा ने छोटी-छोटी कन्याओं का विधिवत पूजन किया। उन्होंने कन्याओं को तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाई तथा उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान सभी ने मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन का विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। यह परंपरा नारी शक्ति के सम्मान, पवित्रता और देवी स्वरूप के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। विद्यालय में इस आयोजन के माध्यम से नन्हे विद्यार्थियों को भारतीय



◆ नन्हे विद्यार्थियों ने जाना भारतीय संस्कृति का महत्व

◆ चेयरमैन वरिंद्र नरियाल व प्रधानाचार्य राकेश राणा ने किया कन्याओं का सम्मान

संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों से परिचित कराने का प्रयास किया गया।

इस विशेष आयोजन में किंडरगार्टन सेक्शन के सभी अध्यापकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पूरे आयोजन के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भारतीय संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं से जोड़ना भी है। इस प्रकार के आयोजन बच्चों में श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर यह कन्या पूजन कार्यक्रम नवरात्रि की पवित्र भावना, नारी शक्ति के सम्मान और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का सुंदर संदेश देकर संपन्न हुआ।

सम्मेलन अभिलाषी विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, 580 प्रतिभागियों ने लिया भाग

पारंपरिक खेती और आधुनिक तकनीक पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अभिलाषी विश्वविद्यालय चैलचौक में आयोजित तीन दिवसीय द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। जलवायु स्मार्ट कृषि एवं पशु स्वास्थ्य के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश से आए लगभग 580 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, कृषि उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की गई।

सम्मेलन के दौरान युवा शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, प्रगतिशील किसानों और स्थानीय सहायता समूहों को विचार साझा करने का अवसर मिला। विशेषज्ञों के व्याख्यान, शोध पत्र प्रस्तुतियां, पोस्टर प्रदर्शनी और नवाचार प्रदर्शन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे। प्रतिभागियों ने कृषि एवं पशुपालन



के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी समाधान विकसित करने पर विचार-विमर्श किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति डॉ. ललित अभिलाषी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मौसम चक्र में तेजी से हो रहे बदलाव कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को मिलकर जलवायु अनुकूल कृषि की दिशा में काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि शोध को प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उसके व्यावहारिक परिणाम किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों के बीच संतुलन स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण के साथ उत्पादन क्षमता बनाए रखी जा सकती है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. आर.के. अभिलाषी ने अपने संदेश में सम्मेलन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक तापवृद्धि के दौर में सतत कृषि और उन्नत पशु चिकित्सा विज्ञान को धरातल पर लागू करने के लिए निरंतर अनुसंधान और नवाचार जरूरी हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन युवा शोधकर्ताओं को नई दिशा प्रदान करते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विश्वास जताया कि सम्मेलन से निकले शोध निष्कर्ष और सुझाव पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों तथा पशुपालकों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

उत्कृष्ट शोधार्थियों को किया सम्मानित

समापन सत्र में उत्कृष्ट शोध पत्र और पोस्टर प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को प्रति-कुलाधिपति डॉ. ललित अभिलाषी तथा कुलपति प्रो. एच.के. चौधरी ने स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मेलन के संयोजक प्रो. पी.सी. शर्मा ने सभी प्रतिभागियों, सहयोगियों और कुरुक्षेत्र से आए साहस सोसाइटी के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलाधिपति डॉ. आर.के. अभिलाषी, प्रति-कुलाधिपति डॉ. एल.के. अभिलाषी, कुलपति प्रो. एच.के. चौधरी, कुलसचिव डॉ. कपिल कपूर, डॉ. नर्वदा अभिलाषी, डॉ. प्रोमिला अभिलाषी और नरेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

एना मारिया की दुनिया दीवानी

क्रोएशियाई फुटबॉलर एना मारिया मार्कोविक को दुनिया की सबसे खूबसूरत फुटबॉलर माना जाता है। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग भी 2.3 मिलियन है। हालांकि, एना मार्कोविक खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत फुटबॉलर नहीं मानती हैं।



रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में शुभमन गिल पर होगी निगाहें

पहले दौर में पंजाब की ओर से नहीं खेल पाए थे भारतीय टीम के कप्तान

एजेंसी, मुल्लांपुर

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में वापसी रविवार से देशभर में शुरू होने वाले इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट के दूसरे दौर का मुख्य आकर्षण होगी। गिल पंजाब के पहले दौर के मैच में नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में भारत की अंडर19 टीम के पूर्व कप्तान उदय सहारन ने टीम की कप्तानी की। इस मैच में पंजाब ने असम के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए थे। सत्र के दूसरे दौर में पंजाब का सामना छत्तीसगढ़ से होगा। गिल का हाल में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 334 रन बनाए। गिल ने दूसरे वनडे में 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए और इस प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।



ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में कर्नाटक ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल के नेतृत्व में अलूर में सौराष्ट्र का सामना करेगा। इस मैच में उसे बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण की कमी खलेगी जिन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। कर्नाटक को हालांकि चोट से उबरने वाले प्रमुख तेज गेंदबाज विद्वथ कावेरप्पा और वैशाक विजयकुमार की वापसी से मजबूती मिलेगी। ग्रुप बी में शीर्ष पर काबिज हैदराबाद की टीम आंध्र के खिलाफ अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगी। उसने पहले मैच में त्रिपुरा को पारी और 40 रन से हराकर बोनस अंक हासिल किया था। ग्रुप सी में दिल्ली और सेना की टीम अपने शुरुआती मैचों में मिली हार से उबरने की कोशिश करेंगी। उनका सामना क्रमश: गुजरात और बंगाल से होगा। गुजरात और बंगाल ने अपने पहले मैचों में जीत हासिल की थी। बंगाल ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को नौ विकेट से हराया था। ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश ने बिहार को पारी और 267 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और अब उसका मुकाबला गोवा से होगा। दूसरी तरफ गोवा अपने पहले मैच में बड़ौदा के खिलाफ पारी और 135 रन की हार से उबरने की कोशिश करेगा। प्लेट ग्रुप में अनुभवी घरेलू क्रिकेटर नीलम ओबी सिक्किम के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश की कप्तानी करेंगी। अरुणाचल राज्य क्रिकेट संघ में प्रशासनिक संकट के कारण अपना पहले दौर का मैच नहीं खेल पाया था।

ग्रुप डी में हिमाचल का मुंबई का होगा मैच

ग्रुप डी में मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे के बिना खेलेगी जो चोटिल हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इस मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम का हिस्सा हैं। मुंबई ने दिव्यांश सक्सेना और अंगकृष रघुवंशी को टीम में शामिल किया है। म्हात्रे और जायसवाल की अनुपस्थिति में मुंबई को मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

रमेश बन सकते हैं बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य

अजीत अगरकर की जगह लेने की दौड़ में आगे

एजेंसी, मुंबई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को बीसीसीआई की सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जा सकता है। उन्हें अजीत अगरकर की जगह जिम्मा मिलने की संभावना है। फिलहाल प्रज्ञान ओझा अंतरिम आधार पर चयन समिति के चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। पोवार ने जूनियर सिलेक्शन कमेटी के पद के लिए भी इंटरव्यू दिया था। शुरुआत में उन्हें जूनियर चयन पैनल का चेयरमैन बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन बाद में उन्हें सीनियर चयन समिति में शामिल करने पर विचार किया गया। सीनियर चयन समिति के पद के लिए इंटरव्यू देने वाले अन्य उम्मीदवारों में बरौदा के पूर्व खिलाड़ी कॉनर विलियम्स और जैकब मार्टिन भी शामिल थे। वहीं, कर्नाटक के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोडा गणेश को जूनियर चयन समिति का चेयरमैन बनाए जाने की संभावना बताई जा रही है।



कमेटी में पोवार के नाम पर बनी सहमति

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने 14 अक्टूबर को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। इस दौरान चार से पांच उम्मीदवारों से बातचीत की गई, जिनमें भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर भी शामिल थे। कमेटी ने पोवार के नाम पर सहमति जताई है। पोवार ने भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे खेले हैं। वह मुंबई के पूर्व भारतीय स्पिनर हैं। इसके अलावा, वह दो अलग-अलग कार्यकाल में भारतीय सीनियर विमेन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। रमेश पोवार ने 10 नवंबर 2015 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया था।

स्पोर्ट्स विंडो

चामिंडा वास बने दिल्ली कैपिटल्स के नए गेंदबाजी कोच



एजेंसी, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने 2027 सत्र से पहले श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वास पिछले दो सत्रों से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे मुनाफ पटेल की जगह लेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी नियुक्ति की घोषणा की। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'विश्व कप विजेता और श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक। टाइगर टेरिटरी में आपका स्वागत है, कोच।' श्रीलंका के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में शामिल वास ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में गेंद और बल्ले, दोनों से योगदान दिया। वह श्रीलंका की ओर से टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम 111 टेस्ट मैचों में 355 विकेट दर्ज हैं। वहीं, एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह श्रीलंका के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 322 एकदिवसीय मुकाबलों में 400 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में भी वास ने टेस्ट क्रिकेट में 3,089 और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,025 रन बनाए। वास मुख्य कोच सौरव गांगुली के नेतृत्व वाले दिल्ली कैपिटल्स के नए कोचिंग दल का हिस्सा होंगे।

जयवर्धने ने छोड़ा मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच का पद



एजेंसी, मुंबई। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है। आईपीएल के 2027 सत्र से पहले उनके इस फैसले के साथ फ्रेंचाइजी के साथ उनका एक दशक लंबा जुड़ाव समाप्त हो गया है। जयवर्धने ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2024 से 2026 तक टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह 2017 से 2022 तक भी इस पद पर रहे थे। उनके कार्यकाल में मुंबई इंडियंस ने तीन आईपीएल खिताब जीते। मुंबई इंडियंस ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस ने आज घोषणा की है कि महेला जयवर्धने मुख्य कोच का पद छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही 'वन फैमिली' के साथ उनका एक दशक लंबा जुड़ाव समाप्त हो रहा है।' मुंबई इंडियंस ने कहा, 'इस पद पर अपने दोनों कार्यकालों के दौरान 2017 से 2022 तक और फिर 2024 से 2026 तक उन्होंने फ्रेंचाइजी की संस्कृति को आकार देने, टीम के भीतर मजबूत माहौल विकसित करने और अनुशासन, सहयोग तथा टीम को सर्वोपरि रखने की सोच को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। '

भारत-वेस्टइंडीज टी-20 से पहले वैभव ने लिखा-मुझे अब भी भरोसा



एजेंसी, नई दिल्ली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी-20 मैच से पहले एक और पोस्ट की है। उन्होंने शुक्रवार रात को इंस्टाग्राम पर लिखा, स्टिल बिलीविंग यानी अब भी भरोसा है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को विंडीज की टीम के खिलाफ इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। हालांकि, वैभव टीम में हैं। वैभव ने 4 दिन पहले चौथे टी-20 मैच से पहले भी एक स्टोरी पोस्ट की थी। उसमें उन्होंने 'इंतजार करिए' लिखा था। उनकी उस पोस्ट को 9 लाख 69 हजार यूजर्स ने लाइक किया था। हालांकि, उस मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। वैभव सूर्यवंशी अब तक खेले 8 मैचों में 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बना चुके हैं। वैभव के नाम 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। वे टी-20 क्रिकेट में 4 शतक लगा चुके हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में शीर्ष क्रम को दिखाना होगा दम

एजेंसी, रायपुर। पहले मैच में असफल रहे भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रविवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अधिक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारतीय टीम पहले मैच में एक समय संकट में दिख रही थी। उसने अपने चार विकेट 19 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद पदार्पण कर रही निक्की प्रसाद और दीप्ति शर्मा ने 82 रन की साझेदारी करके टीम को चार विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को सहजता से लिया जिससे वह संकट में पड़ गए। जिम्बाब्वे की तरफ से ऑफ स्पिनर न्याशा ग्वांज़ुरा ने पावरप्ले में तीन विकेट लिए। भारत के चोटी के बल्लेबाज अब दूसरे मैच में इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले मैच में कप्तान स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अनुष्का शर्मा और पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाई थी। मंधाना का यह पूर्णकालिक कप्तान के रूप में पहला मैच था जिसमें बल्लेबाज के रूप में वह नाकाम रही और अब वह आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए उत्सुक होंगी। (अनंत ज्ञान)

अश्विन ने जायसवाल को वनडे टीम से बाहर करने पर उठाए सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने यशस्वी जायसवाल को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला के लिए टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे इस सलामी बल्लेबाज के आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा की। जायसवाल को वनडे टीम में नहीं चुना गया जो अश्विन को नागवार गुजरा। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर शुभमन गिल आखिरी दो वनडे नहीं खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को चुना जाना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता है।' उन्होंने कहा, 'मैं शुभमन गिल और केएल राहुल की स्थिति को समझ सकता हूं। लेकिन यशस्वी जायसवाल को तो खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे उसका आत्मविश्वास टूट रहा है। अगर आप उसकी बल्लेबाजी देखें तो वह दो-तीन साल पहले



कहा- टीम में जगह न मिलने से आत्मविश्वास पर पड़ सकता है असर

की तरह बल्लेबाजी नहीं कर रहा है।' जायसवाल ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे श्रृंखला के आखिरी मैच में 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए थे। उन्हें विराट कोहली के चोटिल होने के कारण टीम में लिया गया था। अश्विन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे जब भी संभव हो तब इस युवा सलामी बल्लेबाज को मौका दे। उन्होंने कहा, ''वह रन मशीन था। अगर उसका आत्मविश्वास टूट रहा है, तो टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को चाहिए कि जब भी संभव हो तब उसे मौका मिले।

हांगकांग सिक्सेस में क्रुणाल करेंगे भारत की कप्तानी

एजेंसी, हांगकांग। भारतीय ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या हांगकांग सिक्सेस 2026 में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उनकी जगह गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को सात सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। क्रुणाल की अगुवाई वाली भारतीय टीम में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, टी. नटराजन और कुलवंत खेजरोलिया शामिल हैं। टीम में इंडियन प्रीमियर लीग का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के कई विकल्प मौजूद हैं। छह खिलाड़ियों के प्रारूप वाले इस तेज गति के टूर्नामेंट में भारतीय टीम इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर चुनौती पेश करेगी। भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी उनके करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण है।



डेनमार्क ओपन में भारतीय चुनौती समाप्त

तन्वी शर्मा और त्रीसा-गायत्री को क्वार्टर फाइनल में मिली हार

एजेंसी, ओडेंस

डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। महिला एकल में तन्वी शर्मा और महिला युगल में त्रीसा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद को हार का सामना करना पड़ा। भारत की आखिरी उम्मीद तन्वी शर्मा को महिला एकल क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर एक और शीर्ष वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने 21-15, 21-13 से हराया।

38 मिनट तक चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज तन्वी ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं। इससे पहले महिला युगल में भारत की त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को मलेशिया की पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन के खिलाफ 14-21, 21-17, 21-11 से हार झेलनी पड़ी। विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान





पर काबिज भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की और पहले गेम के मध्यांतर तक 11-7 की बढ़त बना ली। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पहला गेम आसानी से अपने नाम किया। हालांकि, विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर मौजूद मलेशियाई जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर दिया। निर्णायक गेम में पर्ली और थिनाह ने दबदबा बनाते हुए भारतीय जोड़ी को उलटफेर करने का मौका नहीं दिया। मलेशियाई जोड़ी ने इसी महीने जापान में हुए एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में भी त्रीसा और गायत्री को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था। इससे पहले भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे। इनमें पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, लक्ष्य सेन तथा आयुष शेट्टी शामिल हैं।

पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर तक जगह बनाई, लेकिन वहां उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन एलेक्स लानियर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

आठवें वेतन आयोग ने तेज की सुझाव जुटाने की प्रक्रिया



एजेंसी, मुंबई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़े पांच बड़े अपडेट सामने आए हैं। आयोग देश के विभिन्न शहरों में बैठकें कर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव जुटा रहा है। हाल ही में बेंगलुरु, जयपुर और चंडीगढ़ में बैठकें संपन्न हुई हैं, जबकि 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में बैठक आयोजित की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को ज्ञापन जमा कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, आयोग में सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव के नोटिस भी चर्चा में हैं। हालांकि, इन बैठकों का मतलब वेतन वृद्धि या फिटमेंट फैक्टर पर तत्काल फैसला होना नहीं है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर, यानी मई 2027 के आसपास अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इसके बाद केंद्र सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और अंतिम मंजूरी के बाद ही नए वेतन, भत्तों तथा पेंशन संबंधी बदलाव लागू हो सकेंगे। ऐसे में कर्मचारियों को नई वेतन व्यवस्था के लिए अभी इंतजार करना होगा। उन्हें वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी अटकलों के बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

प्रियागोल्ड और डोडला डेयरी पर एफएसएसएआई सख्त

प्रियागोल्ड बिस्कुट में पशु चारे का चोकर इस्तेमाल करने का आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य उत्पादों की जांच के दौरान बिस्कुट, दूध और किशमिश सहित कई उत्पादों की गुणवत्ता में खामियां सामने आई हैं। इनमें सूर्या फूड एंड एग्रो के लोकप्रिय ब्रांड प्रियागोल्ड बिस्कुट में पशु चारे में इस्तेमाल होने वाले चोकर के उपयोग का आरोप प्रमुख है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की है। बिस्कुट जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ में इस तरह की कथित अनियमितता सामने आने से उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

इसके अलावा डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध के नमूने में निर्धारित मानकों के अनुरूप वसा की मात्रा नहीं पाई गई। दूध में फैट की मात्रा उसके पोषण और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार होती है। ऐसे में निर्धारित मानकों से कम वसा मिलने पर



एआई निर्मित चित्र।

उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं, यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स की पीली किशमिश में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाने का मामला भी सामने आया है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की मौजूदगी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है, इसलिए इनके इस्तेमाल और निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

एफएसएसएआई ने इन मामलों के अलावा नरपाधम फूड्स, सन रिजेज हेल्थ केयर्स और मेसर्स शाह कांतिलाल जयंतिलाल सहित अन्य कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

आईडीबीआई में हिस्सेदारी घटाने से रोकने वाला कानून नहीं : वित्त मंत्रालय

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के कानूनी अधिकार को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 के विधायी इतिहास और दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है कि सरकार को बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने या बेचने का अधिकार है। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2003 में संसद में सरकार की हिस्सेदारी घटाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए यह प्रावधान अंतिम कानून का हिस्सा नहीं बना। मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर, 2018 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश की नीति पर सरकार लगातार काम करती रही है। इसी क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। यह सौदा फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी के साथ 52,878.08 करोड़ रुपये में प्रस्तावित है।

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 19,510 करोड़ रुपए पार

एजेंसी, मुंबई

एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 18,641 करोड़ रुपये था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) भी करीब 10 प्रतिशत बढ़कर 34,619 करोड़ रुपये पहुंच गई। पिछले साल की समान तिमाही में यह 31,550 करोड़ रुपये थी। बैंक का परिचालन लाभ 5.6 प्रतिशत बढ़कर 29,483 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कुल राजस्व बढ़कर 48,450 करोड़ रुपये हो गया। बैंक की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया। सितंबर 2026 के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 1.11 प्रतिशत रह गया, जो पिछली तिमाही में 1.17 प्रतिशत था।

बैंक की जमा राशि 18.8 प्रतिशत बढ़ी

बैंक के सकल अग्रिम सालाना आधार पर 16.3 प्रतिशत बढ़कर 32.19 लाख करोड़ रुपये हो गए, जबकि कुल जमा राशि 18.8 प्रतिशत बढ़कर 33.27 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इन आंकड़ों से बैंक के कारोबार में विस्तार और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिलते हैं।

जबाब

मस्क के आरोपों को सरकार और रिलायंस ने किया खारिज

प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते, कानून का पालन जरूरी: अंबानी

एजेंसी, मुंबई

एलन मस्क के आरोपों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के उपग्रह इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। कंपनी का कहना है कि उसे किसी भी प्रतिस्पर्धी कंपनी से डर नहीं है और वह भारतीय बाजार में स्टारलिंक समेत सभी कंपनियों का स्वागत करती है। हालांकि, रिलायंस ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में कारोबार करने वाली प्रत्येक घरेलू और विदेशी कंपनी को देश के कानूनों, सुरक्षा मानकों और नियामकीय नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कंपनी के मुताबिक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी विकास को गति देने में मदद मिलती है।



उपग्रह इंटरनेट से बढ़ेंगे विकल्प

भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं का विस्तार दूरदराज के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहाड़ी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और उन स्थानों पर जहां पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क पहुंचाना कठिन है, वहां ऐसी सेवाएं इंटरनेट संपर्क का बेहतर विकल्प बन सकती हैं। स्टारलिंक जैसी कंपनियों के प्रवेश से बाजार में विकल्प बढ़ने और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज होने की संभावना है।

स्टारलिंक विवाद पर रिलायंस का दोटूक जवाब

दरअसल, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्टारलिंक भारत में अपनी व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया से गुजर रही है। इसी बीच एलन मस्क ने भारत में सेवा शुरू करने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सामाजिक माध्यम पर संकेत दिया था कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी हित स्टारलिंक की राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। इन टिप्पणियों के बाद भारतीय दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा, नियामकीय प्रक्रियाओं और विदेशी कंपनियों के लिए कारोबारी अवसरों को लेकर बहस तेज हो गई। रिलायंस और जियो का पक्ष है कि भारत में कारोबार करने वाली सभी कंपनियों के लिए नियम समान होने चाहिए। उपग्रह इंटरनेट सेवाओं के संचालन में सुरक्षा संबंधी शर्तें, लाइसेंस, स्पेक्ट्रम के उपयोग और नियामकीय मंजूरियों का विशेष महत्व है।